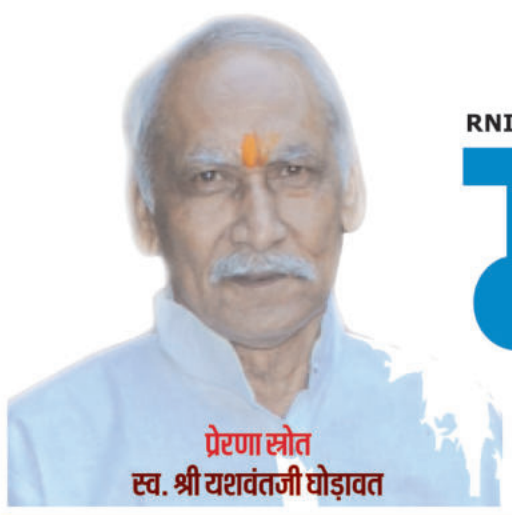


RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार



अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह बनाओ जो जलती जाती है, लेकिन जाते-जाते लोगों के जीवन में उजाला कर जाती है।

गौर गोपाल दास

वर्ष-09, अंक - 01 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 22 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

क्या नेरेटिव के जरिए भारत में सत्ता परिवर्तन संभव है...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा



निःसंदेह अहिंसक आंदोलन के जरिए स्वतंत्र भारत में आपको सत्ता का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना कहां तक उचित है।

पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बहुत अधिक प्रचलन में आया है ''रिजींम चेंज'' जिसका अर्थ है ''तख्ता पलट''। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आंदोलित है। विपक्ष का आरोप है कि, केंद्र सरकार चुनावी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा है कि, हां हम रिजिम चेंज चाहते हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र आंदोलनरत है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध का एसआईआर सहित किसी मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। ये लोग देश में तख्तापलट चाहते हैं और चुनाव के बिना सरकार बनाना चाहते हैं जबकि भारत में यह संभव नहीं है।

भारत में दो ही तरीके से सरकार बदलना संभव है, पहला यह कि, सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे या दूसरा आम चुनाव में जनता सरकार को नकार दें तथा विपक्षी पार्टी को चुन ले और भारत में फिलहाल ये दोनों ही स्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि सरकार को सहयोगी दलों के साथ लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। वहीं आम चुनाव 2019 में होना है।

लगातार तीसरे चुनाव में पराजय के बाद विपक्षी दलों की छटपटाहट को लेकर आम जनता का कहना है कि, विपक्षी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करें यह उनका अधिकार है। लेकिन किसी भी अलोकतांत्रिक तरीके के साथ सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करना न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी हानिकारक है। पिछले दिनों सीजेपी के आंदोलन के बाद ये खबरें आई कि, इनके आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की जा रही है और ये विदेशी शक्तियां भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये खबर सही है तो निःसंदेह देश के स्वस्थ लोकतंत्र के साथ ही देश की बढ़ली हुई अर्थव्यवस्था को रोकने का कुठिंत प्रयास है जो कोई भी आम भारतीय नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारत आज दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो कई वैश्विक शक्तियों को खटक रही है और वे नहीं चाहते कि, भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार निरंतर बढ़ती रहे। इस प्रकार की घटनाओं के बाद ''रिजिम चेंज'' की कोशिशे भले ही नाकाम हो जाए लेकिन अर्थव्यवस्था की तेजी पर ब्रेक अवश्य लग सकता है। देश में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित आंदोलन और कुछ विपक्षी दलों द्वारा उनका समर्थन एक गंभीर चिंता का विषय है। जहां तक छात्रों के हितों की बात है तो नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक तो ठीक इसके बाद उनका निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त से होते हुए देश के शीर्ष नेतृत्व व संवैधानिक संस्थाओं से है और इनके पैरोंकार इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी बतला रहे हैं और रिजिम चेंज के लिए हिंसक क्रांति को आवश्यक बतला रहे हैं। जिसमें वे रक्तपात को भी जरूरी मान रहे हैं और नेपाल, बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं। भारत में संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हिंसक क्रांति का आह्वान सर्वथा अनुचित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है लेकिन साथ ही राज्य को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि, वह देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पर उचित प्रतीबंध लगा सके।

भारत में व्यवस्था का विरोध तो जायज है लेकिन सत्ता परिवर्तन की असली ताकत आम जनता के वोट में ही है। आम जनता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखती है, विश्लेषण करती है और समय आने पर वोट के माध्यम से अपना फैसला सुनाती है।

अगर विदेशी ताकतों के जरिए भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर भारत की अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा करने की कोशिशें की जा रही है तो निःसंदेह विपक्ष को इन कोशिशो का साथ देने से बचना चाहिए। क्योंकि दल से बड़ा राष्ट्र है और इसी भावना के साथ वे सत्ता प्राप्ति कर सकते हैं। अगर राष्ट्र से बढ़कर राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा को ऊपर रखा तो देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ सकती हैं। अगर विपक्षी दल सरकार की किसी बात से असहमत है तो सरकार को सुझाव दे सकते हैं, उसका शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर बात रिजिम चेंज, यानी तख्ता पलट की आती है तो इसका मतलब है विदेशी षड्यंत्र रचा जा रहा है और विदेशी फंडिंग के माध्यम से देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नफरत या असंतोष को भड़का रहे हैं...!

वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजु ने भी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि, फ्रांस और बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं जैसी ही एक साजिश देश में भी रची गई थी। भारत विरोधी गिरोह और कुछ राजनेताओं के युवाओं को उकसाने व सड़कों पर हिंसा फैलाने के लिए यह साजिश रची थी। लेकिन वे यह भूल गई कि, भारत न तो बांग्लादेश है और न हीं फ्रांस है भारत में सत्ता परिवर्तन केवल चुनाव के जरिए ही संभव है।

प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रधानमंत्री ने किया नमन



नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर देश की सुरक्षा और सेवा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान देशवासियों की स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक माध्यम एक्स पर संदेश जारी कर कहा कि पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर अंकुश लगाने, आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की आन-बान और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीर पुलिसकर्मियों के त्याग, साहस और कर्तव्यनिष्ठा को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में पुलिस बल के योगदान को याद किया गया तथा शहीद जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

भारत में बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हो सकते - सुवेंदु अधिकारी



नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशहित में सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर काम करने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार बदलने का उचित तरीका केवल लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के हालात का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति भवन या संसद में अचानक प्रवेश कर सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति पैदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि देश में इस तरह की कोई घटना होती है, तो 80 प्रतिशत लोग इसका विरोध करेंगे। उनके अनुसार, राजनीतिक बदलाव संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही होने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील को लोकतंत्र मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विजयादशमी कार्यक्रम के दौरान सभी राजनीतिक दलों से देशहित में मिलकर काम करने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया था। यह अपील ऐसे समय आई है, जब केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक और परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत की आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर अधिक निर्भर था, लेकिन अब देश 50 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।

आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 12वें स्थान पर था, जबकि अब वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अन्नामलाई, पुलिस की कार्रवाई गलत



कोयंबटूर। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी तथा उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार को सीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि सवाल उठाने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में रखना चाहिए।

पत्रकारों से बातचीत में अन्नामलाई ने कहा कि संभव है कि वह सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के तरीकों और उसकी कुछ गतिविधियों से सहमत न हों, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी दल को सवाल उठाने और अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी से कानून के शासन को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। ऐसी कार्रवाई से विरोध की आवाज दबने के बजाय और मजबूत हो सकती है।

सौरव दास और आशुतोष रंका पर जंतर-मंतर पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने के आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी।

अन्नामलाई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने के अधिकार का भी समर्थन किया।

भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद-रूबियो

नई दिल्ली, एजेंसी।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है। भारत दौरे के दौरान एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि समझौते से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देना बाकी है और आने वाले कुछ सप्ताह में इस पर सहमति बन सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौते के तहत भारत को बेहतर शुल्क दरों का लाभ मिल सकेगा।

रूबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों के साथ रूस से तेल खरीद, पाकिस्तान के साथ संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और क्वाड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। रूस से तेल खरीद के सवाल पर उन्होंने यूक्रेन युद्ध के पांचवें वर्ष में प्रवेश का उल्लेख करते हुए प्रतिबंधों के व्यापक प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने रूस पर तत्काल नए प्रतिबंध नहीं लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में वैश्विक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के साथ व्यापार समझौते से संबंधित मुद्दों पर भी प्रगति होगी।

अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और भारत विरोधी नफरत की घटनाओं पर रूबियो ने कहा कि ऐसी घटनाएं अज्ञानता और नफरत से जुड़ी हैं, जो विभिन्न समाजों में देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत विरोधी भावना व्यापक नहीं है और अमेरिकी समाज ऐसी घटनाओं का विरोध करता है।

क्वाड देशों के नेताओं की बैठक को लेकर रूबियो ने उम्मीद जताई कि इसका आयोजन इस वर्ष के अंत से पहले मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन के सम्मेलन के दौरान हो सकता है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की संभावना भी जताई गई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपने संबंधों को उन्होंने उत्कृष्ट बताया।



जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के दौरे के संबंध में रूबियो ने कंपनी की तेल शोधन क्षमता, वेनेजुएला से तेल आपूर्ति के नए विकल्पों और अमेरिका में निवेश जैसे विषयों पर चर्चा करने की बात कही।

पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों पर रूबियो ने कहा कि रणनीतिक और भौगोलिक कारणों से अमेरिका के लिए पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी उल्लेख किया और कहा कि इन संबंधों के माध्यम से भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान में मदद मिल सकती है।

रूबियो ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए इसकी तुलना जर्मनी की नाजी सरकार की पनडुब्बियों द्वारा अपनाई गई रणनीति से की। उन्होंने कहा कि अमेरिका समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है और ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखेगा।

बम धमाका मामला: दोषियों को पैरोल, फैसले पर राजनीतिक विवाद

चेन्नई। तमिलनाडु में वर्ष 1998 के कोयंबटूर सिलसिलेवार बम धमाकों के पांच दोषियों को 60 दिन की पैरोल दिए जाने के फैसले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम सरकार के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं, विदुथलाई चिरुथैगल काची ने इसे लंबे समय से जेल में बंद कैदियों के मामले में सकारात्मक कदम बताया है।



सरकार ने मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनप्पा उर्फ मोहम्मद हसन, मोहम्मद अजम और नवाब खान को 60 दिन की पैरोल दी है। अधिकारियों के अनुसार, निजी कारणों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और 25 से 30 वर्ष तक जेल में रहने को फैसले का आधार बनाया गया है। हालांकि, भाजपा का कहना है कि धमाकों की गंभीरता को देखते हुए इन कारणों को पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

फरवरी 1998 में कोयंबटूर में सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए थे। इन घटनाओं में 58 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। धमाके भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की चुनावी सभा से पहले हुए थे। इस मामले में 22 लोगों को दोषी ठहराया गया था।

तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने सामाजिक माध्यम एक्स पर सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निजी कारण किसी आतंकवादी हमले की गंभीरता को कम नहीं कर सकते। उनके अनुसार, यह घटना राज्य के इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। भाजपा नेता वनथी श्रीनिवासन ने भी सरकार से सवाल किया कि पांचों दोषियों को पैरोल देने का निर्णय किन परिस्थितियों में और किसकी सलाह पर लिया गया। उन्होंने कानून मंत्री से इस मामले में स्पष्टीकरण देने की मांग की। भाजपा नेताओं ने आशंका जताई कि ऐसे फैसलों से कानून के शासन में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

दूसरी ओर, विदुथलाई चिरुथैगल काची के नेता और सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने पैरोल देने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विजय और कानून मंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से जेल में बंद 22 मुस्लिम कैदियों की रिहाई की मांग कर रही है।

वन्नी अरसु के अनुसार, छह जून को पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इन कैदियों की रिहाई का अनुरोध किया था।

सलमान के घर की रेकी, फिर अभिनेता टाइगर श्रॉफ को बनाया निशाना

मुंबई।

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस जांच के दौरान नए खुलासे सामने आने की खबर है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले के आरोपियों का शुरुआती निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि फिल्म जगत की कोई बड़ी हस्ती थी। आरोपियों ने मुंबई पहुंचने के बाद अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। हालांकि, वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना बदल दी और बाद में टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया।

रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपियों ने सलमान खान के आवास के आसपास की स्थिति का जायजा लिया था। घर के बाहर भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने वहां हमला करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर 18 अक्टूबर को पांच गोलियां चलाई गईं। इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ का सलमान खान के साथ काम करना भी इस हमले के पीछे एक वजह हो सकती है। मामले में पुलिस की जांच जारी है।



सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा है। बिश्नोई समाज में काले हिरण को पूजनीय माना जाता है। इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान को धमकी दे चुका है और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करता रहा है।

वर्ष 2018 में जोधपुर में अदालत में पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। वर्ष 2022 में सलमान के पिता सलीम खान को सुबह की सैर के दौरान धमकी भरा पत्र मिला था। इसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की चेतावनी दी गई थी। वर्ष 2023 में सलमान खान के कार्यालय को भी धमकी भरा संदेश भेजे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद वर्ष 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलीबारी की थी। इन घटनाओं के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

ताजा घटनाक्रम के बाद भजन गायक अनूप जलोटा ने भी सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी है। बताया गया है कि टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना 18 अक्टूबर को उस समय हुई, जब वे फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे। घटना के समय करणवीर मेहरा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बजाज सहित मनोरंजन जगत से जुड़े कई लोग वहां मौजूद थे।

विवादों में घिरता जा रहा फोर लाइन रोड, अधिकारियों की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह

बिना मुआवजा भुगतान के कार्य शुरू, ग्रामीणों ने कई जगहों से ठेकेदार को खदेड़ा



कसारबड़ी में कार्य छोड़ सारंगी के आसपास कार्य किया शुरू।



भाजपा जिलामंत्री सुखराम मोरी ने ठेकेदार के लोगों को बिना मुआवजा राशि के भुगतान के कार्य करने से रोका।



कसारबड़ी में आदिवासी पार्टी के धर्मेंद्र डामोर ने ठेकेदार की मशीनों को बंद करवाकर कार्य बंद करवाया।

माही की गूंज, पेटलावद।

कार्य स्वीकृत होने के बाद से लगातार विवादों में चला आ रहा टीमरवाणी थांदला से बदनावर मार्ग एक बार फिर विवादों में है। यहां मामूली मुआवजा राशि को लेकर किसान कई बार आंदोलित होकर कलेक्टर कार्यालय घेर चुके है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से आन लाईन बैठक में शामिल होकर चार गुना मुआवजा देने की घोषणा की गोली देकर किसानों की हड़ताल खत्म करवाई थी। लेकिन एक बार फिर जब धरातल पर निर्माण कार्य की एजेंसी ने कार्य शुरु किया तो एक बार फिर मार्ग का निर्माण सुर्खियों में आ गया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद कसारबड़ी क्षेत्र से ठेकेदार के लोगों को कार्य करने से रोका गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियो का कहना है कि, प्रशासन की ओर से अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई न ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चार गुना मुआवजा राशि के लिए कोई सुचना-पत्र तक नहीं आया। ऐसे में रोड निर्माण शुरू करना सरकार और ठेकेदार की मनमानी के चलते कार्य शूरू नहीं करने दिया जाएगा। आदिवासी पार्टी के धर्मेंद्र डामोर सहित भाजपा के जिला मंत्री सुखराम मोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। जिसमें ठेकेदार के लोगों को बिना मुआवजा राशि के भुगतान के कार्य शुरू करने से रोका जा रहा है।

लगभग 81 किलोमीटर 38 सौ करोड़ की लागत से बनना है रोड़

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-752डी) के तहत बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 80.45 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन कॉरिडोर की कुल लागत 3,839.42 करोड़ है, जो उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ेगा। इस परियोजना को 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। जिससे यात्रा के समय में लगभग 1 घंटे की कमी आएगी। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी जारी हैं।

धरातल पर सड़क निर्माण शुरू

अब तक नक्शे और योजना में नजर आ रहा बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन (एनएच-752डी) धरातल पर आकर निर्माण का स्वरूप लेने लगा है। बदनावर पेटलावद के बीच सारंगी के पास निर्माण एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। शुरुआती चरण में सड़क पर मोरम डालकर लेवलिंग की जा रही है। सड़क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से उज्जैन महाकाल लोक तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनेगी, बल्कि माही नदी के समीप में विकसित हो रहे पीएम मित्रा पार्क के लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। वहीं माही नदी के पास कुछ लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क निर्माण का काम करने पहुंचे ठेकेदार को काम करने से मना किया है।

चार गुना मुआवजा लेकिन पुरानी गाइड लाइन, कई किसान होंगे बर्बाद

वैसे तो विकास कार्यों की भेट चढ़ने वाली जमीनों के मालिकों को इतना पैसा मिलता है कि, उनका जीवन सुधर जाता है लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग है। मार्ग निर्माण की भेट चढ़ रही जमीनों के मुआवजा भुगतान के निर्धारित गाइड लाइन पुरानी होने से लोगों को पर्याप्त मुआवजा राशि नहीं मिल रही है। कई किसानो की जमीन की रजिस्ट्री का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। कई किसान सरकार की चार गुना मुआवजा राशि को स्वीकार कर राशि ले चुके है लेकिन कई किसान अब भी जमीन में मिलने वाले मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं है। मामूली मुआवजा राशि मिलने से नाराज किसानो ने जमीन देने से मना कर दिया।

किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने बताया कि, मुआवजा राशि के नाम पर किसानो को ठगा गया है पुरानी गाइड लाइन से मुआवजा राशि मंजूर नहीं है। किसान यूनियन इसको लेकर फिर से सड़को पर उतरने के लिए तैयार है, साथ ही हम न्यायालीन प्रक्रिया के माध्यम से भी लड़ाई कर रहे है जिसके लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जबकि इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर में एक पीआईएल पहले से लगी हुई है।

जय-जय श्री राम और आतिशबाजी के साथ रावण दहन

माही की गूंज, बामनिया।



दशहरा पर्व पर ग्राम पंचायत बामनिया के तत्वधान में प्रति वर्ष अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक लगभग 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। मंगलवार को स्थानीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा रावण दहन कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की गई, रावण का 41 फीट से अधिक ऊंचाई का पुतला बनवाया गया। आयोजन को लेकर मैदान में आने वाले हजारों दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी और आतिशबाजी से कोई नुकसान नहीं हो इसके लिए रावण से कुछ दूरी पर बैरिकेटिंग की गई। रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए हजारों लोगों का सैलाब उमड़ा और ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीणजन रावण दहन देखने पहुंचे। रावण दहन से पूर्व लगभग एक घंटे तक आसमानी आतिशबाजी की गई जिससे पूरे आसमान रंग-बिरंगी नजर आने लगा। इस दौरान पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जिसके बाद ग्राम पंचायत उपसरपंच बृजभूषण सिंह परिहार, जनपद सदस्य सोहन डामर व पूर्व उपसरपंच अजय जैन ने रावण के पुतले में अग्नि देकर दहन कार्यक्रम सम्पन्न किया। भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष बल तैनात कर आयोजन को सफल बनाया और किसी प्रकार की अनहोनी या विवाद नहीं होने दिया।

कार्यक्रम के दौरान सरपंच रामकन्या मखोड़ ने बताया कि, आने वाले समय में आयोजन के साथ अन्य आयोजन भी जोड़े जायेगें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्यनारायण शर्मा, अजा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष सचिन बासोड, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारी व ग्राम पंचायत के कई पंचगण भी उपस्थित रहे।

कन्या पूजन और हवन के साथ मां दुर्गा की आराधना

माही की गूंज,सारंगी। नो दिनों तक आस्था से सराबोर रहा नवदुर्गा उत्सव, जो सोमवार को नवमी के साथ संपन्न हो गया। सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। घरों और पूजा पंडालो में विधि विधान से हवन, पूजन और कन्या भोज के आयोजन हुए। मां दुर्गा के जयकारो से वातावरण भक्तिमय रहा। 9 दिनों तक चला धार्मिक आयोजन रास गरबा और डाडियों की रौनक के बाद मां की विदाई की बेला आ गई। श्रद्धालुओं ने नम आंखों और अगले वर्ष फिर आने की कामना के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। नवदुर्गों उत्सव के अंतिम दिन नवमी पर श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिधात्री की पूजा अर्चना एवं परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। घरों में कन्या पूजन कर भोजन कराया गया और उपहार भेट किये गए। मंदिरों एवं गरबा पंडालो मे विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समापन हुआ।



समय से पहले ही जलकर खाक हुआ पुतला

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे से पहले ही रावण का पुतला जलकर खाक हो गया। शहर के इंद्रपुरी इलाके में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान पुतले में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे पुतले को अपनी चपेट में ले लिया। पुतले में लगे पटाखे भी फूटने लगे, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आयोजकों के सामने दशहरे पर रावण दहन की परंपरा पूरी करने की चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि, आयोजकों ने तुरंत नए पुतले को तैयार करने का काम शुरू कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, इंदौर के इंद्रपुरी इलाके में दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही थीं। इसी दौरान रावण के पुतले में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुतले में आग लगते ही कुछ ही देर में लपटें तेज हो गईं और पूरा पुतला जलने लगा। रावण के पुतले में पटाखे भी लगाए गए थे। आग की चपेट में आने के बाद पटाखे अचानक फूटने लगे। पटाखों की आवाज से आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया और इलाके में हलचल मच गई।

रावण के पुतले में आग लगने और पटाखे फूटने की घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। दशहरे के आयोजन की तैयारियों के बीच इस तरह पुतले का जल जाना आयोजकों के लिए भी परेशानी का कारण बन गया। जिस पुतले का दशहरे के दिन विधि-विधान से दहन किया जाना था, वह आयोजन से पहले ही जलकर खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में रावण दहन की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



इंद्रपुरी इलाके में दशहरे पर रावण दहन का आयोजन भाजपा विधायक मधु वर्मा की टीम की ओर से किया जाता है। इसी आयोजन के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा था। तैयारियों के बीच पुतले में आग लगने से पूरा कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई। पुतला जलकर खाक होने के बाद आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दशहरे से पहले दूसरा पुतला तैयार करने की थी। रावण दहन दशहरे के आयोजन का अहम हिस्सा होता है, ऐसे में समय रहते नई व्यवस्था करना जरूरी हो गया।

घटना के बाद आयोजकों ने देर किए बिना नया रावण बनाने का काम शुरू कर दिया। टीम की कोशिश है कि दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा को पूरा किया जा सके। अचानक हुई इस घटना के कारण तैयारियों में बदलाव करना पड़ा है। फिलहाल, पुतले में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आयोजकों ने नया पुतला तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि दशहरे पर रावण दहन का आयोजन किया जा सके।

नौवें दिन माता की भक्ति में झूमे श्रद्धालु

माही की गूंज, भामल। नवदुर्गा नवयुवक मित्र मंडल भामल के तत्वावधान में नौवें दिन भव्य गरबा रास का आयोजन धूमधाम के साथ हुआ। गरबा रास में बड़ी संख्या में क्षत्रिय राजपूत समाज भामल सहित क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देर तक माता की आराधना में लीन होकर डांडिया रास किया। शानदार संगीतमय प्रस्तुति ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। नवरात्रि के नौवें दिन आयोजित इस भव्य गरबा रास में पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।



आम्बुआ-बोरझाड में हुआ रावण दहन

माही की गूंज, आम्बुआ।



अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया गया। जिसके तहत राक्षस राज लंका नरेश रावण के पुतले का सार्वजनिक रूप से आतिशबाजी कर दहन किया गया। तत्पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले मिल कर विजयादशमी की बधाई दी।

भगवान श्री राम द्वारा लंकेश नरेश अधर्मी रावण को युद्ध में परास्त कर अयोध्या लौटने पर विजय पर्व मनाया गया था। तभी से हर वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का सार्वजनिक रूप से आतिशबाजी कर दहन किया जाता आ रहा है। इसी कड़ी में परंपरानुसार आम्बुआ में भी प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी पुराने पत्थर कारखाने के मैदान पर 30 फुट ऊंचे पुतले का दहन आतिशबाजी कर सरपंच रमेश रावत द्वारा किया गया। इसी तरह समीप ग्राम बोरझाड में पहली बार रावण के पुतले का दहन धूम धाम से आतिशबाजी कर सरपंच प्रतिनिधि आशिष कटारिया द्वारा किया गया। प्रथम बार कार्यक्रम आयोजित होने से क्षेत्रीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। आम्बुआ तथा बोरझाड में कार्यक्रम स्थल पर छोटे-छोटे व्यापारियों ने खिलोने तथा खाने पीने का अच्छा व्यवसाय किया। ग्रामीण क्षेत्र अडवाडा,झौरा, हीरापुर, वडी, भोरदू, मोटाउमर, देकालकुआ, झीरण, सेवड, हरदासपुर, आम्बी अगौनी, इटारा,टैमाची,चिचलाना आदि से भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

उड़ती खबर: गांजे की फसल बोने की शिकायत, पुलिस पहुंची वीडियो बनाया, खेत मालिक ने हटाए पौधे

वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिये रुपए और मामला किया रफा-दफा

माही की गूंज, खवासा।



कोई भी कितनी भी अंदरूनी बात हो अगर कोई बात या वाक्या होता है तो वह धीमे-धीमे आम चर्चाओं में बदलकर उड़ती हुई हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचती जरूर है।

कुछ ऐसा ही मामला खवासा चौकी अंतर्गत गांजे के पौधे बोने एवं शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा वीडियो बनाने से लेकर मामले को भांजगड़ी के साथ निपटाने का हुआ पुरा सिलसिला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

उड़ती चर्चा की खबर ये है कि, पिछले दिनों फॉरेस्ट एवं पुलिस खवासा को गुप्त शिकायत प्राप्त हुई थी कि, खवासा-थांदला मार्ग पर स्थित एक ग्राम के निवासी ने अपने खेत में गांजे की फसल की उपज की जा रही है और पौधे भी बड़े हो गए हैं। उक्त शिकायत पर पुलिस भी जानकारी अनुसार मौके पर पहुंची और खड़ी गांजे की फसल के पौधे के वीडियो-फोटो मोबाइल में कैद किए, जिसके बाद पुलिस आ गई। वहीं खेत मालिक ने पुलिस के जाते ही खेत में लगे गांजे के लगे पौधे को जमीन से उखाड़कर नष्ट कर दिए गए। लेकिन बात जब पुलिस व पुलिस के मोबाइल में कैद हो गई ऐसे में बिना लिए-दिए तो ऐसा मामला रफा-दफा होना नामुमकिन ही है।

क्षेत्र में उड़ती चर्चा अनुसार सामने आ रहा है कि, पुलिस ने खेत मालिक को चौकी परिसर में बुलाया और भांजगड़ियों के माध्यम से फोटो-वीडियो प्रूफ के साथ लगभग 70 से 80 हजार रुपए में पुलिस द्वारा मामला रफा-दफा किया गया।

उड़ती चर्चा में यह भी सामने आ रहा है कि, संबंधित खेत मालिक के पास पुलिस को मामले को रफा- दफा करने वाली समझौते की राशि नहीं होने के चलते बाजार में अपनी रकम को गिरवी या बेचकर लाया और पुलिस को उक्त राशि दी गई।

माही की गूंज उक्त मामले की पुष्टि नहीं करता है लेकिन क्षेत्र में चल रही चर्चा तभी उड़ती है जब कुछ न कुछ होता है। मामले में हमारे प्रतिनिधि ने एक फॉरेस्टकर्मी से बात की तो उन्होंने भी नाम न बताने व लिखने की शर्त पर बताया, मामला सही है और फॉरेस्ट विभाग ने नहीं खवासा पुलिस ने उक्त मामले को भांजगडी के साथ रफा-दफा किया।

डेढ़ साल से अधूरा पड़ा आंगनवाड़ी भवन

मध्यान्ह भोजन फर्जीवाड़े में फंसा समुह ही दे रहा भोजन

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पेटलावद विकास खंड में विकास पहिया तेजी से घूम रहा है लेकिन पहिया इतना घिस गया है कि विकास कार्यों की समय सीमा ही नहीं रही । गूंज के पिछले अंक में हमने ग्राम पंचायत बोडाइता के महुडीपाड़ा में स्थित किराए के मकान संचालित आंगनवाड़ी का बड़ा खुलासा किया जहां तीन साल से मध्यान भोजन नहीं मिलने का गम्भीर मामला सामने आया था। मामले की पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि सरकार ने यहां आंगनवाड़ी स्वीकृत कर दी निर्माण भी शुरू हुआ लेकिन लगभग डेढ़ साल से आंगनवाड़ी भवन का कार्य अधूरा होकर कार्य बंद है, ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत से पूछने पर बताया जा रहा है कि बजट नहीं है। वही अधूरे पड़े भवन का लोग शौचालय के रूप में उपयोग कर रहे है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ियों की ये स्थिति सरकार के मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।

घोटाले में आरोपी रहा सम्भाल रहा भोजन व्यवस्था

जिस आंगनवाड़ी में तीन साल से मध्यान भोजन बच्चों को नहीं दिया जा रहा उसके माध्यम भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सहेली सहायता समूह की है, जो कि पेटलावद जनपद में हुआ चर्चित मध्यान भोजन घोटाले में शामिल था ओर इस मामले में जेल भी जा चुका है। मामला का खुला मंगलवार को जब हुआ जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जन सुनवाई कार्यक्रम में की , आवेदन में बताया गया कि सहेली सहायता समूह के सदस्य जो अभी मध्यान भोजन देने का काम ले रखा है वो पूर्व में फर्जीवाड़े के चलते जेल तक जा चुका है ओर मामला आज तक न्यायलय में चल रहा है।

अभी तक किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं

मामला उजागर होने ने बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जब सुनवाई में आवेदन देकर लिखित शिकायत की लेकिन इस मामले ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की । ग्रामीण पप्पू सिंगाड ने बताया कि, हमको जन सुनवाई कार्यक्रम में अधिकारियों से आश्वासन मिला था कि इस मामले कार्यवाही करेंगे लेकिन लगभग दस दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही की जानकारी हमको नहीं मिली न ही कोई कार्यवाही की जानकारी हमको दी गई । मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रितिका पाटीदार से चर्चा की तो उन्होने बताया कि में मामला संज्ञान में आया है में इसको जल्द जल्द की दिखावाती हु।

सोचिए तीन साल से आंगनवाड़ी में बच्चों को समूह द्वारा मध्यान भोजन नहीं देने जैसा गम्भीर मामला सामने आता है खबर प्रकाशित होती है,जन सुनवाई तक लिखित में मामला पहुंचता है लेकिन अधिकारी मामले के सामने आने के 15 दिन बाद तक मामले को दिखवाने की बात कह रहे है। जिससे साफ है कि अधिकारी गंभीर मामलों में भी कितना गंभीर है।

भुगतान जांच का विषय

इस मामले में सबसे बड़ा खेल पिछले तीन सालों में मध्यान भोजन नहीं मिलने के बाद उस आंगनवाड़ी के मध्यान भोजन व्यवस्था के भुगतान का है जिसकी जांच होना जरूरी है। क्योंकि भुगतान नहीं हुआ मतलब भोजन व्यवस्था नहीं थी ,तो महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार क्या कर रहे थे, अगर भोजन नहीं मिला ओर कागजों पर खानापूर्ति कर भुगतान किया गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है किनकी रिपोर्ट पर भुगतान किया गया। अगर मामला सही नहीं है तो ग्राम पंचायत ने आम सभा में किए प्रस्ताव ठहराव में तीन साल से भोजन व्यवस्था नहीं होने की पुष्टि कैसे की। ऐसा केवल एक या कुछ आंगनवाड़ीयों में हो रहा है या मध्यान भोजन के नाम पर एक ओर बड़ा घोटाला जनपद पंचायत क्षेत्र पेटलावद के अंतर्गत किया जा रहा है जिसकी जांच जरूरी है। नई एसडीएम रितिका पाटीदार के समक्ष ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अब तक मैदान में उनसे कोई बड़ी कार्यवाही नहीं देखी गई है।



- डेढ़ साल से अधूरी पड़ी आंगनवाड़ी, लोग और जानवर कर रहे नित्य क्रिया।

दर्दनाक हादसा: डूबने से तीन मासूमों की मौत, चुई में मातम

माही की गूंज, सनापुर/कुर्दनपुर



रानापुर क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है ग्राम पंचायत चुई के पटेल फलिया में कुएं में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई, मृतक बच्चों के परिजनों का बुरा हाल है, वहीं गांव में हर आंख नम है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे मंगलवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच अपने-अपने घरों से निकले थे। इसके बाद वे कुएं तक कैसे पहुंचे और किस परिस्थिति में हादसा हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना रावण दहन के बाद प्रशासन को मिली, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। बचाव कार्य शुरू कराया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले दो बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले गए, तीसरे बच्चे को निकालने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

विवेक पिता महेश राठौड़, मयंक पिता शैलेश चौहान, विजय पिता बाबू चंगोड़ तीनों बच्चों की उम्र करीब 9 से 10 वर्ष बताई जा रही है। जिन घरों में बच्चों की हंसी-खुशी से रौनक रहती थी, वहां अब मातम पसरा है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तीन मासूमों की मौत ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बिना मुडेंर कुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चौकियों पर हुआ शस्त्र पूजन



माही की गूंज, सारंगी।

विजयादशमी दशहरे के अवसर पर सारंगी पुलिस चौकी पर परम्परागत शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। चौकी प्रभारी दीपक राव दैवरे ने विधि-विधान से पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजन किया गया। उन्होंने पुलिस के शस्त्र, वाहन और चौकी परिसर में विराजित मशीनरी की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि, शांति और अपराध मुक्त क्षेत्र की कामना की। शस्त्र पूजन हिंदू धर्म में शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पुलिस विभाग में यह परम्परा है कि, दशहरे के दिन अपने शस्त्रों की पूजा कर कर्तव्य पथ पर सच्ची निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया जाता है। इस अवसर पर सारंगी चौकी का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

माही की गूंज, करवड़।

चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह दोहरे के द्वारा पंडित लोकेंद्र शर्मा की उपस्थिति में विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। पंडित लोकेंद्र शर्मा के द्वारा शस्त्रों पर माल्यार्पण कर दिप प्रचलित कर पूजा संपन्न करवाई। असत्य पर सत्य और धर्म पर अधर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर पुलिस चौकी करवड़ में पारंपरिक विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया गया। चौकी प्रभारी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, यह पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने के साथ अपने कर्तव्यों का और समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम में पुलिस चौकी स्टाफ से प्रधान आरक्षक थान सिंह मुवेल, हर्ष कैमा, आरक्षक प्रवीण शर्मा, मनजीत सिंह राठौर सहित स्टाफ उपस्थित रहा।



बदलेगा मौसम, २० जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

भोपाल। अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं दिन में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। अब 22 अक्टूबर को भी प्रदेश के कई जिलों में बादल बरसने और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम समेत 20 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बौछरें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं, प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र के मुताबिक, भोपाल में 22 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। यहां गरज-चमक और आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच अगले चार दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के इन 20 जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 अक्टूबर को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नरसिंहपुर और सागर में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछरें पड़ सकती हैं। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और गरज-चमक की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं, बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।



भोपाल में 33 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान

राजधानी भोपाल में 22 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान हवा की औसत गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

अगले चार दिनों में 2 डिग्री तक गिर सकता है रात का पारा

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। ऐसे में रात और सुबह के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना सभी जिलों में नहीं है। विभाग ने कुछ जिलों में ही बारिश और गरज-चमक का पूर्वानुमान जताया है।

पिछले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई?

मौसम विभाग की 21 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के बाकी संभागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा।

बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो गैरतगंज में सबसे ज्यादा 29 मिमी बारिश दर्ज की गई। खंडवा में 24 मिमी और उदयनगर में 20 मिमी बारिश हुई। भीकनगांव में 16 मिमी, हरदा में 8.9 मिमी, सरदारपुर में 8 मिमी और बड़नगर में 7 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा आगर और मकसूदनगढ़ में 5-5 मिमी, उज्जैन और तराना में 4-4 मिमी तथा बेगमगंज में 3 मिमी बारिश हुई। खिरकिया में 2.6 मिमी, राजगढ़, जीरापुर और देवरी-सागर में 2-2 मिमी बारिश दर्ज की गई। भोपाल में 1.8 मिमी, सारंगपुर में 1.2 मिमी, केसली में 1.1 मिमी और ब्यावरा व खिलचीपुर में 1-1 मिमी बारिश हुई। बदनावर में 0.3 मिमी और इंदौर में 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

रात में कहां रही सबसे ज्यादा और सबसे कम ठंड?

न्यूनतम तापमान के मामले में अमरकंटक सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, पचमढ़ी में 16.6 डिग्री, मंदसौर में 16.8 डिग्री और दतिया में 17 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके उलट शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में 22.8 डिग्री, बैरसिया में 22.2 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 21.7 डिग्री और सिवनी में 21.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

सीहोर में 37 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चले हवा के झोंके

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सीहोर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके दर्ज किए गए। 21 अक्टूबर को धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास, उज्जैन, आगर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, गुना और सागर जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली या बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं।

कार्यालय नगर परिषद, पेटलावद जिला-झाबुआ (म.प्र.)

दूरभाष/फैक्स नं. 07391-265439 Email - cmopetlawad@mpurban.gov.in

क्रमांक/26/2485 पेटलावद, दिनांक 15/10/2026

"ई-निविदा सूचना"

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत टेकेदारोंध्सप्लायर्स से आनलाईन निविदायें प्रतिशतध्आईटम दर पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर कमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_543582	CONSTRUCTION OF R.C.C. NALI IN W.NO. 08 FROM HARCHAND KE MAKAN SE NAALE TAK (BUILDING SOR) {II ND CALL}	1. 06 माह 2. 1.72 लाख	1. 1000/- 2. 4000/-	
2	2026_UAD_543583	CONSTRUCTION OF R.C.C. SEWER PIPE AND PAVER BLOCK WORK IN W.NO. 14 PAPU DAGAL KE MAKAN SE PAVAN ATKAN KE MAKAN TAK (BUILDING SOR) {II ND CALL}	1. 06 माह 2. 5.09 लाख	1. 1000/- 2. 10000/-	30.10. 2026
3	2026_UAD_543584	WATER BODY REJUVENATION WORK OF PAMPAWATI RIVER UNDER AMRUT 2.0 SCHEME (BUILDING SOR) {II ND CALL}	1. 09 माह 2. 39.05 लाख	1. 5000/- 2. 29285/-	
4	2026_UAD_543585	BEAUTIFICATION AND GARDEN WORK UNDER VISHESH NIDHI SCHEME IN W.NO. 12, 13 AND 15 (BUILDING SOR) {I ST CALL}	1. 09 माह 2. 42.74 लाख	1. 5000/- 2. 32100/-	14.11. 2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptender.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद पेटलावद जिला-झाबुआ (म.प्र.)

नौसिखियों की राजनीति, कमीशन का गुब्बार, रावण को नहीं हुआ स्वीकार

माही की गूंज, थांदला। मुकेश भट्ट

जिले के साथ ही राजस्थान,गुजरात और अन्य प्रांतों सहित मालवा अंचल में प्रसिद्ध थांदला का एक मात्र विजयादशमी मवेशी मेला जो पुरे जिले के मेले में प्रथम पंक्ति में आता है।

इस बार बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों की खुशियों,आशाओं पर ग्रहण लगा गया। रावण दहन कार्यक्रम में रावण का पुतला बनाने से लेकर, उसमें भरी जाने वाली आतिशबाजी सामग्री के साथ पुतला दहन से पूर्व किए जाने वाले रंगारंग आतिश बाजी कार्यक्रम नौसिखियों की राजनीति ओर कमीशन खोरी का शिकार हो गया। बताते है प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुतला बनाने से ले कर रावण पुतला में भरे जाने वाले पटाखे और पुतला दहन से पूर्व की जाने वाली आतिशबाजी को लेकर बड़ी कमीशन खोरी की गई। अनुभवहीन लोगों के हाथों में आतिशबाजी सौंपी गई जिसके चलते आतिशबाजी सामग्री सीधे आसमान में न जाते हुए रावण पुतले के दाये हाथ के कंधे के नीचे सीने में जा लगी जिससे पलभर में रावण स्वाहा हो गया।

पिछले कुछ वर्षों से रावण दहन के पहले आतिशबाजी रावण के पुतले से 500मीटर की दुरी पर की जाती थी। इस बार नगरपरिषद के अनुभवहीन अधिकारी ने इस और ध्यान नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा फटाके पर डाल रहे हैं।

राम रथ रह गया बाजार में

परंपरा अनुसार रावण दहन हेतु स्थानीय बड़ा रामजी मंदिर से राम,लखन,हनुमान आदि के रूप में संवार कर बच्चों को रथ में जुलूस के माध्यम से लाया जाता है। मेला प्रांगण में राम रथ की अगवानी कर उन्हें दहन स्थल के बेरीकेट्स में ससम्मान ले जाया जाता है। जहाँ पहले हनुमान प्रतीकात्मक रूप से लंका दहन करते है पश्चात उसके तय समय पर राम रथ से उतर कर रामजी का वेश धारण किया बच्चा रावण दहन करता है। इस से पूर्व लगभग आधे से पौन घंटा रावण दहन स्थल पर आतिशबाजी की जाती है। किंतु इस बार राम रथ बाजार से जब रावण दहन स्थल पर पहुंच रहा था उससे पूर्व ही रावण ने कमीशन का गुब्बार फोड़ दिया जिसके चलते रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचे ग्रामीण ओर नगर से पहुंचने वाले आमजन में निराशा मिश्रित आक्रोस देखने को मिला।



जवाबदारों को जरा भी रंज गम नहीं

नगर में 65 वर्षों की परम्परा में पहली बार इस तरह की अप्रत्याशित घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रति क्रियाओं का दौर शुरू हो गया। वही पुतला दहन स्थल पर मौजूद नगर परिषद सीएमओ, मेला अधिकारी, उपयंत्री आदि पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी साध ली। तो जनप्रतिनिधि बजाय इस लापरवाही की जिम्मेदारी नगर परिषद पर लेने के मंच से कहते नजर आए कि, आतिश बाजी से रावण दहन हो गया 'बोलो जय जय सिया राम'। जबकि नगर परिषद के जिम्मेदार जन प्रतिनिधियों से राम रथ में सवार होकर आए राम लक्ष्मण सहित जुलूस में आए श्रद्धालुओं से इस अप्रत्याशित घटना हेतु क्षमा मांगना चाहिए थी।

निविदा प्रक्रिया अल्प समय में

प्रतिवर्ष बाकायदा रावण दहन,मेला में लाइट,टेंट मवेशी का पंजीयन से लेकर क्रय,विक्रय शुल्क हेतु बकायदा निविदाएं काफी समय पूर्व सूचना के साथ निकाली जाती है। किंतु इस वर्ष इन सभी निविदाओं को मात्र 5 दिन पूर्व आमंत्रित कर 'कुल्हाड़ी में गुड तोड़' लेने वाली कहावत चरितार्थ कर ली। सूत्रों की माने तो इस वर्ष के अधिकांश टेंडरों में कोई पार्षदों का अप्रत्यक्ष हाथ रहा। बताने वालो का यह भी कहना हे कि, खास कर आतिशबाजी में बड़ा खेल हुआ है।

संपादकीय

स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था



फ्रांस में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे आगजनी और मॉल व महंगे स्टोरों में लूट तक जा पहुंचा है। निस्संदेह, कथित वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते वैश्विक स्तर पर उपजी आर्थिक विषमता ने अमीरी-गरीबी की खाई को और गहरा किया है। एक ओर जहां व्यापार के केंद्र बने अभिजात्य वर्ग के स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय फल-फूल रहे हैं,वहीं सरकारी अनुदान से चलने वाले शिक्षण संस्थानों की बदहाली जगजाहिर है। यह विषमता विश्वव्यापी है और आक्रोश भी। दरअसल, लोकतांत्रिक सरकारों की जो परंपरागत कल्याणकारी नीतियों की अवधारणा थी, वह नये आर्थिक दौर में मुनाफे पर आधारित व्यवस्था में तब्दील होती गई। राजनेताओं व सत्ता से जुड़े लोगों की शैक्षणिक संस्थाओं के मुनाफे में भागीदारी ने स्थितियों को विषम बनाया है। हालांकि, सत्ताधीशों की विलासिता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन आम जनता चौतरफा आर्थिक दबावों से जूझ रही है। सबसे पहले एक सदी बाद आई कोरोना की महामारी ने विश्व आपूर्ति श्रृंखला को तो बाधित किया ही, सैकड़ों किस्म के रोजगारों को भी खत्म किया। जैसे-तैसे एक साल बाद उस आर्थिक संकट से दुनिया उबरने की कोशिश में थी कि युद्ध ने सब चौपट कर दिया। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पहले रूस-यूक्रेन युद्ध ने बुरी तरह प्रभावित किया। फिर इस्राइल-हमास संघर्ष ने इस संकट को बढ़ाया। इसके उपरांत अमेरिका द्वारा ईरान पर थोपे गये युद्ध ने पूरी दुनिया में ईंधन संकट खड़ा कर दिया। दुनिया के देशों के बजट चरमराए और लोक कल्याण से जुड़ी संस्थाएं और योजनाएं हाशिये पर आ गई। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से ईंधन के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और महंगाई कुलांचे भरने लगी। जो कालांतर सामाजिक असंतोष की वाहक बनी। निस्संदेह, सुनहरे सपने लेकर आगे बढ़ रही युवा पीढ़ी की आशाओं पर इस संकट ने तुषारापात किया। शिक्षा व्यवस्था महंगी हुई और रोजगार के अवसर सिमटते गए। निस्संदेह, दुनिया की महाशक्तियों की निरंकुश व निर्मम नीतियों ने पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को कष्टकारी बनाया है। इसीलिए भविष्य की आशंकाओं ने युवाओं को आक्रोशित किया।

दरअसल, यूरोप के जिन तमाम देशों में फिलहाल आक्रोश की लपटें दिखायी दे रही हैं, उनके मूल में सिर्फ युवाओं का गुस्सा ही नहीं है। इस तपिश में रोटी सेंकने के लिये राजनीतिक दल आतुर दिखायी देते हैं। फ्रांस में जहां दक्षिणपंथी उभार के संकेत दिखायी दे रहे हैं, वहीं कुछ देशों में वाम व श्रमिक संगठन अपने अवसर तलाश रहे हैं। जहां दक्षिणपंथी दल प्रवासियों को अपने-अपने देश की समस्याओं की वजह बता रहे हैं, वहीं वामपंथी दल सत्ता में भागीदारी को आतुर हैं। यह कटु सत्य यह है कि जिन देशों में इस समय आंदोलन उभार पर हैं, उनमें से स्पेन, फ्रांस, इटली,पोलैंड और ग्रीस में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। अत- इन आंदोलनों के राजनीतिक निहितार्थ समझना कठिन नहीं होगा। आम आदमी जहां पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य वस्तुओं की कीमतें और आवासीय महंगाई बढ़ने से आक्रोशित है, वहीं युवा रोजगार संकट से त्रस्त हैं। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखायी दे रहा है। वहीं अल्बानिया में हिंसक रूप ले चुका आंदोलन सिस्टम के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर है। आंदोलनकारियों ने लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों से जुड़े संस्थानों तक को आग के हवाले किया है। दरअसल, समाज में एक ओर अभिजात्य वर्ग की विलासिता बदस्तूर जारी है, वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग को रोटी-कपड़ा-मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्ताधीशों की संवेदनहीनता और लोक कल्याण के वायदों का हकीकत न बन पाना आक्रोश की वजह बन रहा है। कहीं न कहीं कथित सोशल मीडिया ने भी इस तपिश को ईंधन उपलब्ध कराया है। जिसमें दिखाया जा रहा स्वप्नलोक तो लुभावना है, लेकिन हकीकत खुरदरी है। एक तरफ अथाह विलासिता के बिंब हैं, दूसरी तरफ जीवन की मूलभूत जरूरतों का संकट। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रमाणिक व अतिरंजित सामग्री युवाओं को आक्रामक बना रही है। वे विषमता व विसंगतियों के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनका आंदोलन निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा हैक कर लिया जाता है। निस्संदेह, दुकानों को लूटने वाले जेन-ज़ी नहीं हो सकते। मॉस्क व हूडी पहनकर सुपर बाजार व मॉल लूटने वालों की वास्तविक पहचान करने की जरूरत है।

भारत के फैसलों पर चीन का दोहरा रवैया



गौतम बंबावाले

लद्दाख में 28 जगहों की पहचान करके और उन्हें आधिकारिक नक्शे पर चिह्नित करते हुए उनके नाम तय करने के भारत के कदम पर चीन ने त्वरित और कुछ हद तक चिढ़ भरी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गत 13 अक्तूबर को कहा, 'चीन भारत द्वारा प्रचारित तथाकथित तय नामों का कड़ा विरोध करता है' और कहा कि 'यह कदम गैर-कानूनी और अमान्य है'।

भारत के जवाबी कदम उठाने से बहुत पहले ही चीन ने खुद ऐसा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है कि यह उसकी अपनी कार्रवाई की प्रतिक्रिया है। यह खेल का एक जाना-पहचाना तरीका है। चीन जो करे, वह सही; जब वही काम कोई दूसरा करे, तो गलत!

ऐसा लगता है कि भारत का यह कदम चीन को चुभ गया है–तभी तो उसने तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपनी ताकत के घमंड में चीन इस साधारण-से तथ्य को नज़रअंदाज़ कर रहा है कि यह खेल दोनों तरफ से खेला जा सकता है। भारत तो बस उसी काम को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी शुरुआत पहले चीन ने की थी। चीन के कर्ता-धर्ताओं को आने वाले महीनों और सालों में भारत की ओर से ऐसे और भी 'तय नामों'–यह वह शब्द है, जिसका इस्तेमाल खुद चीनी करते हैं–की उम्मीद करनी चाहिए। कृपया यह न भूलें कि कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया था। अगस्त में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं के नाम तय किए थे। गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि यह काम राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके किया गया है।



चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के कुछ और पहलू भी हैं, जिन पर गहराई से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है कि 'चीन ने कभी भी भारत द्वारा एकतरफा एवं गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तथाकथित 'केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख' को मान्यता नहीं दी है'।

इस टिप्पणी से तुरंत ये सवाल उठते हैं = क्या भारत के प्रशासनिक ढांचे में किसी भी बदलाव में चीन के दखल की कोई गुंजाइश है? क्या यह पूरी तरह से भारत का अपना फैसला नहीं है? क्या चीन ने तब आपत्ति जताई थी, जब 2014 में पुराने आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था? साफ़ तौर पर नहीं। तो फिर चीन को ऐसा क्यों लगता है कि 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो उसमें उसकी भी कोई सहमति होनी चाहिए? अनुच्छेद 370 को हटाने पर चीन कैसे आपत्ति जता सकता है, जबकि यह भारत का एक घरेलू प्रशासनिक फ़ैसला था?

जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो दिल्ली ने चीन को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसका भारत-चीन सीमा विवाद के सवालों पर कोई प्रभाव नहीं है। सीमा से जुड़े विवादों पर दोनों देशों के बीच संवाद और वार्ता जारी रखने की ज़रूरत है। फिर भी, शायद पाकिस्तान के उकसावे पर चीन ने इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के गठन पर आपत्ति जताई थी। चीन ने कभी भारत को यह नहीं बताया कि वह अनुच्छेद 370 के तहत मिली विशेष व्यवस्था को खत्म करने का विरोध क्यों कर रहा है। शायद अब समय आ गया है कि चीन इस मामले पर खुलकर बात करे और भारत को बताए कि उसे क्या आपत्तियां हैं। हो सकता है कि चीन ऐसा न करना चाहे, क्योंकि इससे भारत के घरेलू मामले पर उसका रुख सबके सामने आ जाएगा।

बेशक, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब 1987 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया था, तब भी चीन ने उस कदम पर आपत्ति जताई थी। आज भी, जब कभी केंद्र से गए भारतीय नेता उस राज्य का दौरा करते हैं, तो चीन ज़ोरदार आपत्ति जताता है। साफ़ है कि ये आपत्तियां इसलिए हैं, क्योंकि चीन पूरे राज्य पर अपना दावा करता है, जबकि हकीकत यह है कि लगभग पूरे इलाके पर भारत का वास्तविक नियंत्रण है–ज़्यादातर जगहों पर तो मैकमोहन रेखा तक।

क्या लद्दाख के मामले में भी यही सिद्धांत लागू किया जा रहा है? क्या चीन का तर्क यह है कि जब तक सीमा तय और चिह्नित नहीं हो जाती, तब तक भारत अपने ही इलाके में जो कुछ भी करेगा, उस पर–भले ही चीन का कोई विवाद न हो–चीन को वीटो (रोकने) का अधिकार है? यह एक बहुत ही अजीब तर्क है। यहां तक कि चीन को भी यह समझ में आना चाहिए कि यह कितना खोखला है।

यह हमें चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के तीसरे पहलू पर लाता है, जिसमें कहा गया है '...इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि भारत-चीन सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है।' असल बिंदु यही है। भारत उस इलाके पर सवाल उठाता है, जिसे चीन अपना क्षेत्र मानता है। वहीं दूसरी ओर, चीन को उस इलाके पर एतराज़ है, जिसे भारत अपना कहता है। इसीलिए वहां सीमा का सवाल या सीमा विवाद है।

अब ऐसा लगता है कि चीन एकतरफा तौर पर यह कह रहा है कि जिस क्षेत्र को दोनों देश मोटे तौर पर सीमा का पश्चिमी हिस्सा परिभाषित करते हैं, वह चीन का इलाका है। हो सकता है कि यह इस मुद्दे पर अपना पक्ष दोहराने का एक तरीका हो, लेकिन यह काफी बचकाना है। इन मुद्दों पर आगे बढ़ने का तरीका यह है कि आमने-सामने बैठकर खुलकर बातचीत की जाए। हालांकि, 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की सैन्य गतिविधियों के बाद से ऐसी वार्ता बहुत मुश्किल, लंबी और समय लेने वाली हो गई है।

चीन के लिए असली महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ना तभी संभव होगा, जब वह आरोप-प्रत्यारोप, इशारों-इशारों में बात करने और कूटनीतिक भाषा का सहारा लेने के बजाय व्यावहारिक, यथार्थवादी और स्पष्ट रुख अपनाकर ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करे। अपनी भुजाएं फड़काने और अपनी विशाल राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे व्यावहारिक और समाधान खोजने वाला रुख अपनाना चाहिए।

हो सकता है कि इससे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का समाधान न निकले, लेकिन इससे दोनों पड़ोसियों के बीच अधिक स्पष्ट, सीधे और सरल संबंधों की नींव पड़ सकती है।

परंपरा से हटकर सह -जीवन के यक्ष प्रश्न

लिव-इन रिलेशनशिप या सह-जीवन आधुनिक समाज की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो वयस्क बिना किसी कानूनी या पारंपरिक विवाह के एक ही छत के नीचे पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं। यह अवधारणा केवल आधुनिक जीवनशैली नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार है।

यद्यपि 'लिव-इन रिलेशनशिप' शब्द पश्चिमी आधुनिकता की देन लगता है, लेकिन बिना पारंपरिक विवाह के दो वयस्कों का साथ रहना इतिहास में अलग-अलग रूपों में मौजूद रहा है। पश्चिमी समाजों में 1960 और 1970 के दशकों की यौन क्रांति और नारीवादी आंदोलनों के बाद इस व्यवस्था को गति मिली, जिसमें महिलाओं ने 'माय बॉडी, माय चॉइस' का नारा बुलंद किया। महिलाओं की आर्थिक आजादी और गर्भनिरोधक साधनों की सुलभता ने विवाह की अनिवार्यता को कम किया। महान फ्रांसीसी लेखक व दार्शनिक वोल्तेयर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एमिली डू शेटेले तथा फ्रांस के ही प्रसिद्ध दार्शनिक सिमोन द बोउवार और ज्यां-पॉल सार्त्र को पाश्चात्य इतिहास का सबसे चर्चित और प्रभावशाली लिव-इन जोड़ा माना जाता है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार मीडिया पर्सनैलिटी ओप्रा विन्फ्रे और उनके पार्टनर स्टेडमैन ग्राहम 1986 से लिव-इन में रह रहे हैं।

प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह का प्रचलन था, जिसमें माता-पिता की सहमति या किसी धार्मिक अनुष्ठान के बिना स्त्री और पुरुष आपसी सहमति से एक-दूसरे को चुनकर साथ रहने लगते थे। आज भी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी समुदायों में प्रचलित नाता प्रथा के अंतर्गत कोई भी स्त्री-पुरुष अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जातीय समुदायों में स्त्री-पुरुष अपनी मर्जी से विवाह किए बिना साथ रह सकते हैं, जिसको 'घर बैठना' कहते हैं।



यदि भारत के प्राचीन आख्यानों को खंगाला जाए, तो विवाह बंधन में बंधे बिना अनेक विभूतियों के साथ रहने और बच्चे पैदा होने के प्रसंग मिलते हैं। प्राचीन काल से ही व्यक्तिवादियों द्वारा विवाह संस्था को चुनौती मिलती रही है, क्योंकि इसमें हमेशा बंधन में जीना होता है, जबकि सह-जीवन स्वतंत्र इच्छा, विश्वास और आपसी प्रेम पर आधारित है।

दार्शनिक ज्यां-पॉल सार्त्र और सिमोन द बोउवार जैसे विचारकों का मानना था कि यदि पारंपरिक विवाह किसी के लिए मानसिक तनाव या हिंसा का कारण बन रहा है, तो लिव-इन को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, जो बिना कानूनी जटिलताओं (जैसे तलाक की लंबी प्रक्रिया) के अलग होने की आजादी देता है।

कुछ शोध बताते हैं कि वैवाहिक कानूनों की जटिलताओं, भरण-पोषण जैसी बाध्यताओं और तलाक की लंबी प्रक्रियाओं के चलते ही लोग लिव-इन की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। दहेज का भारी खर्च व पारंपरिक विवाह उद्योग के दिखावटी प्रपंचों से विवाह का व्यय क्षमता से अधिक हो जाता है। रही बात सामाजिक मान्यता की, तो आर्थिक आजादी और कैरियर के कारण घर से दूर रहने वाले युवा इसकी परवाह नहीं करते। समाज इसे उच्छृंखल व्यवहार मानते हुए मान्यता नहीं देता है। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अभाव के चलते ऐसे रिश्ते अमूमन ऐसे मोड़ पर खत्म होते हैं, जहां से सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं।

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दों पर जनता से राय मांगी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने लोगों से सुझाव लेने हेतु एक वेबसाइट शुरू की है। सरकारें सह-जीवन व इससे जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और समान नागरिक संहिता के साथ-साथ पारिवारिक एवं यौन हिंसा, संपत्ति के अधिकार व भरण-पोषण, बच्चों की परवरिश व जिम्मेदारी तथा धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव से संबंधित कानून बनाने हेतु रायशुमारी कर रही हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से लिव-इन रिलेशनशिप को सामाजिक संरचना व विवाह और परिवार के पारंपरिक ढांचे में बदलाव के रूप में देखा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी चाहत को सामाजिक बंधनों से ऊपर रखता है। आज की युवा पीढ़ी विवाह जैसी स्थायी संस्था में कदम रखने से पहले भावनात्मक, वित्तीय और शारीरिक अनुकूलता की जांच करने के लिए लिव-इन को एक 'टेस्ट रन' या 'ट्रायल पीरियड' मानती है। कुछ लोग इसे लैंगिक समानता के हक में तथा पारंपरिक विवाह और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ युवा पीढ़ी की बगावत के रूप में भी देखते हैं।



प्रमोद कुमार बाजपाई

भारतीय समाज भले ही इसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों का सहमति से साथ रहना कोई अपराध या पाप नहीं। लंबे समय तक चलने वाले लिव-इन संबंधों को शादी जैसा माना जा सकता है और महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण व भरण-पोषण का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है।

यह देखना अहम होगा कि समाज इसे कब तक एक सामाजिक अपराध की दृष्टि से देखता रहेगा, जबकि सरकार व कानून अपने नजरिये में बदलाव कर रहे हैं। समय आ गया है कि बदलते परिवेश में समाज अपनी मान्यताएं बदले।

हिमालय को बचाने के लिए वैज्ञानिक निगरानी जरूरी



जयसिंह रावत

नेपाल में गत 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है, जो समूचे हिमालय के लिए खतरे की घंटी है। जिस पहाड़ के टूटने से नेपाल और चीन में हजारों लोग मारे गए अथवा लापता हो गए, वह आपदा से कई सप्ताह पहले ही खिसकने लगा था। यूरोपीय सेंटिनल-1 उपग्रह ने 48 दिनों के दौरान उसकी सतह में 40 सेंटीमीटर तक का संचलन दर्ज किया था। इसका अर्थ है कि पहाड़ के भीतर बढ़ती अस्थिरता के संकेत अंतरिक्ष से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें समय रहते प्रभावी चेतावनी में नहीं बदला जा सका। यह खुलासा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) की 13 अक्तूबर को जारी वैज्ञानिक रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, 26 अगस्त की सुबह लगभग 8:37 बजे नेपाल के रसुवा क्षेत्र में 7,227 मीटर ऊंचे लांगटांग लिरुंग पर्वत के उत्तरी हिस्से से लगभग 13.2 करोड़ घनमीटर चट्टान और हिमनद की बर्फ टूटकर नीचे आ गिरी। करीब 1,200 मीटर नीचे ल्हेंदे खोला घाटी में गिरते ही यह विशाल द्रव्यमान चट्टानों, बर्फ, मिट्टी और पानी के प्रचंड प्रवाह में बदल गया। विनाशकारी मलबा-बाढ़ नेपाल-चीन सीमा से गुजरती हुई भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में फैल गई। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि दूरस्थ भूकंपीय उपकरणों ने भी कंपन दर्ज किया।

इस वैज्ञानिक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष उपग्रह से प्राप्त आंकड़े हैं। सेंटिनल-1 की रडार तकनीक ने 7 जुलाई से 24 अगस्त के बीच पर्वतीय ढलान में क्रमिक परिवर्तन दर्ज किया। इस तकनीक को इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार कहा जाता है। इसके माध्यम से बादलों और अंधेरे की परिस्थितियों में भी धरातल की सूक्ष्म हलचलों का आकलन संभव है। हालांकि, 40 सेंटीमीटर का आंकड़ा उपग्रह की दृष्टिरेखा की दिशा में मापा गया संचलन है, न कि पहाड़ के वास्तविक विस्थापन का संपूर्ण माप। फिर भी, यह बढ़ती अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेत था।

वैज्ञानिकों ने एक अन्य धारणा में भी संशोधन किया है। प्रारंभ में इस बाढ़ को हिमनद झील के फटने की घटना माना जा रहा था, लेकिन अध्ययन के अनुसार, इसका प्रमुख कारण आधारशिला का व्यापक रूप से टूटना था। चट्टानें अपने ऊपर स्थित हिमनद की बर्फ को साथ लेकर नीचे गिरीं और इससे विनाशकारी मलबा प्रवाह उत्पन्न हुआ।



वैज्ञानिकों ने कई संभावित कारणों की पहचान की है। इनमें भूगर्भीय दरारें, वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप से उत्पन्न क्षति, स्थायी रूप से जमी भूमि का पिघलना, हिमनदों में परिवर्तन और बर्फ के भार में उतार-चढ़ाव शामिल हैं। बढ़ता तापमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमी बर्फ और चट्टानों के बीच प्राकृतिक बंधन को कमजोर कर सकता है। हालांकि, वैज्ञानिकों ने अभी किसी एक कारण को निर्णायक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इस आपदा ने मौजूदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की सीमाएं भी उजागर की हैं। अधिकांश व्यवस्थाएं वर्षा, नदी के जलस्तर और संभावित बाढ़ पर केंद्रित हैं। लेकिन जब हजारों मीटर की ऊंचाई से करोड़ों घनमीटर चट्टान और बर्फ अचानक टूटकर गिरती है, तब नीचे स्थापित जलस्तर मापक उपकरण पर्याप्त समय पहले चेतावनी देने में सक्षम नहीं होते। नेपाल की घटना में चेतावनी संदेश पहाड़ टूटने के लगभग 38 मिनट बाद भेजे गए। तब तक विनाशकारी प्रवाह कई प्रभावित बस्तियों से गुजर चुका था।

यह चेतावनी भारत, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फरवरी 2021 की ऋषिगंगा-धौलीगंगा आपदा में भी ऊंचाई पर चट्टान और बर्फ का विशाल हिस्सा टूटने से विनाशकारी बाढ़ उत्पन्न हुई थी। इस घटना ने तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना सहित नदी घाटी के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई। केदारनाथ की 2013 की त्रासदी और हिमालय की अन्य घटनाएं बताती हैं कि पर्वतीय आपदाओं का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, लेकिन निचले इलाकों में बसे समुदायों के लिए उनके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं।

उत्तराखंड में वसुंधरा ताल जैसी संवेदनशील हिमनद झीलों की निगरानी की पहल उपयोगी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को केवल झीलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ऊंचे पर्वतीय ढलानों, हिमनदों, अस्थिर चट्टानों और नदी घाटियों का संयुक्त जोखिम मानचित्र तैयार करना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच नियमित वैज्ञानिक समन्वय आवश्यक है।

उपग्रहों से संवेदनशील ढलानों की पहचान करने के बाद वहां भू-संचलन मापक उपकरण, स्वचालित मौसम केंद्र, भूकंपीय संवेदक और नदी प्रवाह निगरानी प्रणालियां स्थापित की जा सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक जानकारी केवल शोध संस्थानों तक सीमित न रहे। इसे जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करके प्रशासन, जलविद्युत परियोजनाओं, सीमावर्ती सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चेतावनी के साथ-साथ सुरक्षित स्थानों, निकासी मार्गों और नियमित अभ्यास की तैयारी भी जरूरी है। नेपाल, चीन और भारत के पर्वतीय जलागम क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए उपग्रह आंकड़ों, मौसम संबंधी सूचनाओं और संभावित खतरों की समयबद्ध साझेदारी अनिवार्य है।

जर्मनी की तकनीक से भरे जाएंगे मंदसौर की सड़कों के गड्ढे

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर की सड़कों पर जगह-जगह हो रहे गड्ढों से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए अब जर्मनी की तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंदौर से आई एक टीम ने मंदसौर शहर की कुछ सड़कों पर गड्ढे भरकर प्रयोग किया।

इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर और सीएमओ पीके सुमन भी मौके पर पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया। यह प्रयोग सफल रहता है और नए मटेरियल के परिणाम बेहतर मिलते हैं, तो पूरे शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए इस मटेरियल का उपयोग करने के लिये नपा बैठक कर निर्णय ले सकती है।

कई सड़कें पूरे साल ही गड्ढे से भरी रहती हैं

वर्षा ऋतु में शहरभर की सड़को पर गड्ढे हो गए हैं। कई सड़कें पूरे सालभर ही गड्ढे से भरी रहती हैं, इसके कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानियां हो रही है। नगर पालिका द्वारा कुछ-कुछ दिनों में कभी कच्चा तो कभी पक्का पेचवर्क किया जा रहा हैं, लेकिन यातायात के अधिक दबाव और बारिश से पेचवर्क बार-बार उखड़ रहा है।

शहर के गड्ढों से स्थाई निजात के लिये अब एक नया प्रयोग शहर में शुरू हुआ है। शहर की सड़कों के गड्ढों को भरने के लिये हुए ट्रायल में जो मटेरियल भरा गया है, उसके लिये संबंधित कंपनी का दावा है कि पैचवर्क के चार घंटे बाद ही यातायात शुरू किया जा सकता है और यह बेहद टिकाऊ है। दावा यह भी है कि जहां नए मटेरियल से पैचवर्क किया जाएगा उस जगह से सड़क नहीं उखड़ेगी भले ही आसपास से पूरी सड़क उखड़ जाएं।

महाराणा प्रताप बस स्टैंड के समीप मार्ग पर कुछ ग ों को भरकर किया प्रयोग

कंपनी के दावे और शहर में टिकाऊ पेचवर्क की मांग को देखते हुए नपा ने इस नए प्रयोग को शुरू करवाया हैं। इंदौर से आई टीम ने सोमवार को महाराणा प्रताप बस स्टैंड के समीप मार्ग पर विमल प्रिंटर्स के सामने हो रहे गड्ढो को भरने का काम किया। इन गड्ढो को भरने के लिये जर्मनी की तकनीक का उपयोग किया गया।

नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, सीएमओ पीके सुमन सहित नपा के इंजीनियर और अधिकारी भी यहां पहुंचे और पेचवर्क की प्रक्रिया देखी, मटेरियल के इस्तेमाल के तरीके की जानकारी ली। सोमवार को कुछ गड्ढो को भरने में इसका प्रयोग किया गया है। इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो आने वाले दिनों में पूरे शहर में इसी मटेरियल से सड़को पर पेचवर्क होगा।

कंपनी का दावा-चार घंटे बाद भारी यातायात का भी असर नहीं होगा

जर्मनी की तकनीक पर आधारित गड्ढों को भरने वाले नए मटेरियल को लेकर संबंधित कंपनी ने दावा किया है कि गड्ढे में मटेरियल भरने के चार घंटे बाद उस स्थान से कितना भी भारी यातायात गुजर जाए, पेचवर्क पर उसका असर नहीं पड़ेगा।



कंपनी के अनुसार, जिस जगह गड्ढा भरा गया है, वहां की मरम्मत इतनी मजबूत होगी कि आसपास की सड़क टूट सकती है, ल ि क न पैचवर्क वाला हिस्सा अपनी जगह बरकरार रहेगा। कंपनी का दावा सही साबित होता हैं तो शहर में बड़ी राहत हो सकती हैं, बार-बार गड्ढे भरने और सड़क की मरम्मत कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। हालांकि, नए मटेरियल की मजबूती और टिकाऊपन का सही आंकलन पैचवर्क के कुछ दिन बाद ही हो सकेगा।

सफल रहा तो प्रयोग पूरे शहर में नए मटेरियल से भरे जाएंगे गड्ढे

नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर किए जा रहे कार्य को देखा। यह प्रयोग सफल रहा तो नगर पालिका द्वारा पूरे शहर की सड़को पर गड्ढो में नए मटेरियल को भरा जाएगा। इंदौर से आए अधिकारियों के अनुसार जर्मनी की तकनीक पर आधारित इस नए मटेरियल का उपयोग भारत में मंदसौर पहला शहर हैं जहां हो रहा हैं। मंदसौर में ही पहला ट्रायल हैं। जिन गड्ढो को भरा गया हैं वह मजबूत रहेंगे भारी यातायात से भी नहीं उखड़ेगा तो फिर पूरे शहर में इसी तरह का पैचवर्क नजर आएगा।

चार घंटे बाद ही यातायात शुरू किया जा सकता है

शहर की सड़को पर पैचवर्क के लिये नए तरह के मटेरियल की कंपनी के कुछ लोग नपाध्यक्ष से मिले थे, कंपनी का दावा है कि नए मटेरियल से सड़कों के गड्ढों में पैचवर्क करने के बाद चार घंटे बाद ही यातायात शुरू किया जा सकता हैं, और यह उखड़ेगा भी नहीं। प्रयोग के तौर पर अभी महाराणा प्रताप बस स्टैंड के समीप सड़क पर गड्ढे भरवाए गए हैं, प्रयोग सफल रहता हैं तो हम पीआईसी में बैठक कर निर्णय लेंगे। यह तकनीक जर्मनी की बताई जा रही है। **-पीके सुमन, सीएमओ नपा मंदसौर**

देश में पहली बार यहां ट्रॉयल हो रहा है

डामर व सीमेंट की सड़कों पर बारिश के कारण गड्ढे हो जाते हैं। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिये जर्मनी के प्रोडक्ट को हमने भारत में तैयार किया है। इस प्रोडक्ट का देश में मंदसौर में पहला ट्रॉयल हैं। इस मटेरियल से सड़क के गड्ढे को भरने के चार घंटे बाद ही यातायात उस मार्ग से शुरू किया जा सकता हैं। कितना भी भारी यातायात हो इस नए मटेरियकल से हुए पेचवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पैचवर्क किया गया है, वहां सड़क नहीं खुदेगी, भले ही आसपास की सड़क उखड़ जाएगी, लेकिन वहां कुछ नही होगा। अभी ट्रायल किया गया है, आगे नपा मंदसौर जो निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। **-राजेश शाह, सदस्य, इंदौर टीम**

टैंकर के पहियों के बीच लेटा युवक

माही की गूंज, रतलाम।





जावरा-उज्जैन मार्ग पर चापाखेड़ा फंटे के समीप भारत पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को 28 वर्षीय मांगीलाल पुत्र प्रभुलाल प्रजापत निवासी ग्राम गुर्जर बरड़िया का शव सड़क पर मिला। शुरुआत में आशंका थी कि युवक किसी वाहन की चपेट में आने से मारा गया। बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वह खड़े टैंकर के पिछले पहिए के आगे खुद लेटता दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैंकर आगे बढ़ता है और पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है।

सीसीटीवी फुटेज में 00.35 सेकंड तक युवक टैंकर के पिछले पहियों के पास खड़ा दिखाई देता है। 00:36 से 00:38 सेकंड के बीच टैंकर रुका रहता है और युवक नीचे झुककर पिछले पहिए के ठीक आगे सड़क पर लेट जाता है। 00:38 सेकंड पर वह पहिए के सामने जमीन पर सीधा लेटा हुआ दिखाई देता है।

इसके बाद 00.39 सेकंड पर टैंकर आगे बढ़ना शुरू करता है। 00.40 से 00.41 सेकंड के बीच टैंकर का पहिया युवक के ऊपर से गुजर जाता है। थाना प्रभारी संतोष चौरसिया ने बताया कि फुटेज में दिखाई दे रहे घटनाक्रम से युवक के खुद पहिए के आगे लेटने की बात सामने आती है, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और टैंकर चालक को इसकी जानकारी थी या नहीं, यह जांच का विषय है।

पोस्टमार्टम के लिए वाहन नहीं मिला, किया जाम

शव बड़ावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो घंटे से अधिक समय तक रखा रहा। पोस्टमार्टम के लिए शव को सिविल अस्पताल जावरा ले जाने के लिए समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने से स्वजन ने नाराजगी जताई। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

कुछ समय के लिए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। पुलिस की समझाइश के बाद एमपीआरडीसी की एंबुलेंस पहुंची। इसके बाद शव को जावरा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

घर लौट रहे युवक को नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली





माही की गूंज, रतलाम। रेलवे स्टेशन से फ्रीगंज रोड बायपास की ओर जा रहे 28 वर्षीय सुनील पुत्र घनश्याम प्रजापत निवासी जूनी कलाल सेरी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली सुनील की पीठ पर कमर के नीचे लगी। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात के दौरान दो फायर किए गए। घटनास्थल पर कारतूस का खाली खोखा मिला है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर दो नकाबपोश दिखाई दिए हैं।

ट्रेन से उतरकर घर लौटते समय हुआ हमला

सुनील दाहोद में रामेश ज्वेलर्स नामक दुकान पर काम करता है। वह सप्ताह में एक-दो बार ट्रेन से रतलाम स्थित अपने घर आता है। सोमवार रात करीब 9 बजे ट्रेन से उतरने के बाद वह अपनी एक्टिवा (एमपी 43 डीवी 3121) से घर जा रहा था। इसी दौरान पुराने माल गोदाम रोड पर पीछे से आए बाइक सवारों ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद सुनील का एक्टिवा से संतुलन बिगड़ा और वह सड़क किनारे चद्दर की दीवार से टकरा गया।

प्रेम विवाह से जुड़ा हो सकता है विवाद

घायल सुनील ने अपने मित्र मनोज पंवार को सूचना दी। मनोज अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और उसे मेडिकल कॉलेज ले गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की। पुलिस को मौके से कारतूस का खाली खोखा मिला है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर दो नकाबपोश दिखाई दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। घायल सुनील ने अपनी पत्नी के पिता कोमल सिंह पंवार उर्फ नाना पर आरोप लगाए हैं। सुनील का करीब छह माह पहले अपने ही मोहल्ले की युवती से प्रेम विवाह हुआ था। हालांकि, इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि मामला जीआरपी क्षेत्र से जुड़ा है। जीआरपी और सिटी पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।

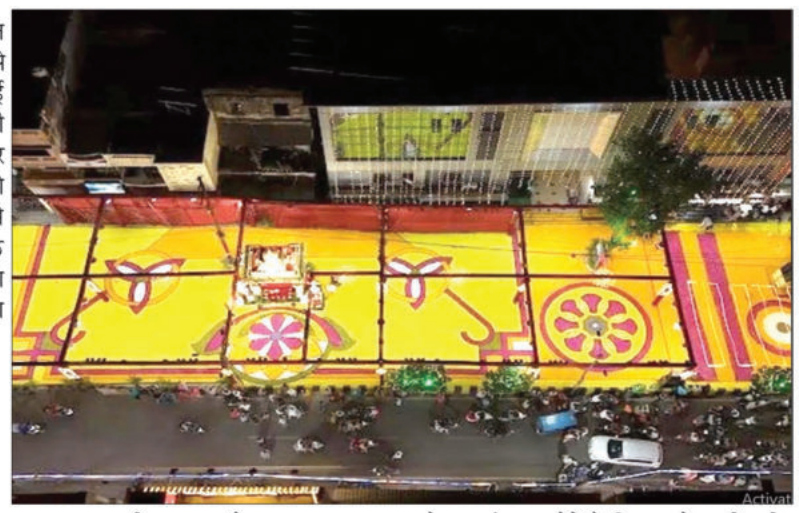
51 क्विंटल फूलों से सजी रंगोली, गरबा महोत्सव के समापन पर उमड़ा जनसैलाब

माही की गूंज, रतलाम।

गरबा की थाप, उत्सव का उल्लास और फूलों से सजी भव्य कलाकृति... रेलवे स्टेशन रोड पर नवयुवक मंडल के गरबा महोत्सव के अंतिम दिन आस्था, कला और रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां 51 क्विंटल फूलों से करीब दो हजार वर्गफीट क्षेत्र में विशाल रंगोली तैयार की गई। फूलों की सजावट से सजी इस आकर्षक कलाकृति को देखने के लिए शाम से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा।

गरबा महोत्सव के समापन पर तैयार की गई इस विशाल रंगोली ने आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले लोगों का ध्यान खींचा। बड़ी मात्रा में फूलों का इस्तेमाल कर इसे आकर्षक स्वरूप दिया गया। विशाल क्षेत्र में फूलों को करीने से सजाकर तैयार की गई रंगोली आयोजकों की मेहनत, रचनात्मकता और आयोजन की भव्यता को दर्शाती नजर आई। इसे देखने के लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे और इसकी सराहना की।

आठ घंटे तक चली तैयारी, फूलों से उकेरी आकर्षक कलाकृति



आयोजक अश्विन जायसवाल ने बताया कि रंगोली तैयार करने में करीब आठ घंटे का समय लगा। इसके लिए 51 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया। करीब दो हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस कलाकृति को आकर्षक रूप देने के लिए फूलों को योजनाबद्ध तरीके से सजाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में फूलों से रंगोली तैयार करना अपने आप में विशेष रहा। आयोजन से जुड़े लोगों ने इसे आकार देने के लिए लगातार मेहनत की, जिसके बाद यह भव्य स्वरूप सामने आया।

शाम से जुटने लगे लोग, देर रात तक रही रौनक

रंगोली को देखने के लिए शाम होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, आयोजन स्थल पर भीड़ भी बढ़ती गई। देर रात तक लोग फूलों से तैयार इस विशाल कलाकृति को देखने पहुंचते रहे। रंगोली के आसपास लोगों की मौजूदगी से उत्सव स्थल पर रौनक बनी रही। लोगों ने इसकी भव्यता और सजावट की सराहना की।

गरबा महोत्सव के समापन पर खास आकर्षण

नवयुवक मंडल के गरबा महोत्सव के अंतिम दिन तैयार की गई यह पुष्प रंगोली आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही। गरबा महोत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के बीच इस विशेष प्रस्तुति ने कार्यक्रम को अलग पहचान दी। फूलों से बनी विशाल रंगोली ने न केवल लोगों को आकर्षित किया, बल्कि आयोजन के समापन को भी यादगार बनाया। शहरवासियों की लगातार आवाजाही ने इसकी लोकप्रियता को दर्शाया।

दो युवतियों समेत 8 लोगों का अपहरण...

भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में पैसों के विवाद ने अपहरण और फिरौती की सनसनीखेज वारदात का रूप ले लिया। एयरोसिटी में रहने वाले दो युवतियों समेत आठ युवक-युवतियों को घर में घुसकर पीटा गया और फिर जबरन गाड़ियों में बैठाकर अगवा कर लिया गया। आरोप है कि अपहरण के दौरान भी पीड़ितों के साथ मारपीट की गई और उन्हें छोड़ने के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली में मौजूद एक दोस्त की सतर्कता अहम साबित हुई। उसकी सूचना पर भोपाल पुलिस हरकत में आई और सभी आठों पीड़ितों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, सभी पीड़ित मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और भोपाल के एक होटल में साथ काम करते हैं। वे गांधी नगर क्षेत्र के एयरोसिटी में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी का पीड़ितों से दो लाख रुपये को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को वारदात की वजह माना जा रहा है। आरोप है कि आरोपी अपने साथियों के साथ पीड़ितों के घर पहुंचा। वहां पहले उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें जबरन दो गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले जाया गया।

पीड़ितों को अगवा करने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर गाड़ी के अंदर भी उनके साथ मारपीट की। इसके बाद रिहाई के बदले 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाया गया। इस दौरान पीड़ितों ने दिल्ली में मौजूद अपने एक परिचित से संपर्क किया और आरोपियों के खाते में रुपये ट्रांसफर करने की बात कही। बातचीत सुनकर दोस्त को शक हुआ कि मामला सामान्य पैसों के लेन-देन का नहीं, बल्कि किसी गंभीर अपराध से जुड़ा हो सकता है। उसने देर किए बिना डायल-112 पर भोपाल पुलिस को सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पीड़ितों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान सभी आठ युवक-युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, वारदात का मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

एसीपी शशांक जैन ने बताया कि गांधीनगर क्षेत्र में अपहरण का मामला आया था। आरोपियों ने आठ लोगों को बंधक बनाकर गाड़ी में घुमाया था और उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस कोई एफआरबी पर सूचना मिली थी उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक गाड़ी समेत तीन आरोपियों को पकड़ लिया है।

मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पैसों के विवाद से लेकर अपहरण और फिरौती की मांग तक पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली में बैठे दोस्त की सतर्कता निर्णायक साबित हुई, जिसकी सूचना से समय रहते पुलिस तक बात पहुंची और आठों लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका।

पशुपतिनाथ मंदिर में शराब पीकर घुसा मुस्लिम युवक

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झोंकने की बड़ी साजिश हुई है और इसके बावजूद जिम्मेदारों की चुप्पी इस आग में घी डालने जैसा काम कर रही है। श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में ही स्थित श्री सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को अपराह्न में एक मुस्लिम युवक शराब के नशे में पहुंच गया। वहां उसने कई गलत हरकतें भी कीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पशुपतिनाथ मंदिर समिति व सिक्योरिटी एजेंसी चुप रही।

मंगलवार को जब इसको लेकर हल्ला मचा तो मंदिर समिति के बजाय सिक्योरिटी एजेंसी ने नई आबादी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जहरीली शराब भी मिली है। इस पूरे मामले ने यहां पर निजी सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है। वहीं हमेशा की तरह मंदिर समिति प्रबंधक की लापरवाही भी उजागर हुई है।

मंदिर की सुरक्षा ही निजी सुरक्षा गार्डों के भरोसे पर

श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को 2012 में ही आईबी ने डेंजर जोन में रखा था और इसे आतंकवादियों की सूची में बताते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई उपाय भी करने को कहा था पर सरकार ने इसके लिए बजट ही नहीं दिया। और अब तो मंदिर की सुरक्षा ही निजी सुरक्षा गार्डों के भरोसे पर है। इनमें से एक भी ट्रेनिंग वाला नहीं दिखता है। न ही ठीक से काम कर रहे हैं। कई बार तो अपनी जगहों से भी गायब ही रहते हैं।



मंदिर में की ऊटपटांग हरकतें

इसका ही नतीजा यह हुआ सोमवार को अपराह्न 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच सारे गेट को पार करता हुआ शराब के नशे में इमरान पुत्र अब्दुल रशीद खलीफा निवासी नयापुरा श्री सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। वहां उसने कई ऊटपटांग हरकतें कीं। जब दूसरे लोगों ने देखकर गार्डों को बुलाया और पकड़कर बाहर लेकर आए।

इसके बाद भी समिति ने सोमवार को कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को पूर्व विधायक यशपालसिंह सिसौदिया ने इस मामले को लेकर सवाल-जवाब किए तो आनन-फानन में मंदिर की सुरक्षा एजेंसी की तरफ से नई आबादी थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया।

अब बड़ा सवाल यही है कि सांप्रदायिक मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसके बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई न कर दबाना भी अपराध की श्रेणी में आता है, इस मामले में मंदिर समिति प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।

केवल शराब के नशे के नाम पर आरोपित को बख्श नहीं सकते

पूर्व विधायक यशपालसिंह सिसौदिया ने कहा कि सिर्फ शराब के नशे के नाम पर आरोपित को बख्शा नहीं जा सकता है। क्या आरोपित का मेडिकल हुआ है, आरोपित के मंसूबे क्या थे, इसके बारे में भी प्रशासन को गंभीरता दिखाना चाहिए, मंदिर परिसर में आरोपित की हरकतें सीसीटीवी फूटेज में कैद हुई होगी।

क्या प्रशासन ने उसको चेक किया है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आरोपित पर सख्त कार्रवाई कर गंभीर धाराओं में कार्रवाई करें। यह घटना मामूली नहीं है, इस प्रकार की घटना से शहर का वातावरण बिगड़ सकता है, शांति भंग हो सकती है, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाएं और आरोपित के षड़यंत्र को भी बेनकाब करे।

मंदिर की सुरक्षा ठेके में गड़बड़ी के आरोप

पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मंदिर समिति प्रबंधक व सिक्यूरिटी एजेंसी के बीच साठ-गाठ के भी आरोप लगते रहते हैं। अभी लक्ष्य सिक्यूरिटी एजेंसी ग्वालियर का ठेका है। पर यहां तैनात महिला व पुरुष सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित नहीं है। अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं।

इसका नतीजा है कि शराब पीकर आरोपित मुख्य द्वार से सहस्त्रेश्वर मंदिर तक पहुंच गया। पूर्व विधायक यशपालसिंह सिसोदिया ने इस घटना के संबंध में एसडीएम शुभम पाटीदार, मंदिर समिति प्रबंधक राहुल रुनवाल से कहा कि सुरक्षा एजेंसी का आवेदन पर्याप्त नहीं है। मंदिर समिति को भी प्रकरण दर्ज कराना चाहिए।

क्या कहते हैं संबंधित?

मंदिर में इस तरह शराब पीकर किसी का घुसना घोर लापरवाही का उदाहरण है। अभी थोड़ी सी लापरवाही में शहर की कानून-व्यघवस्थाा बिगड़ सकती है। मंदिर परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखेंगे।- **विनोद कुमार मीना, एसपी**

मंदिर समिति की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी। यहां देखेंगे कि निजी सुरक्षा गार्डों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है या नहीं, सिक्यूरिटी एजेंसी से भी अप्रशिक्षित गार्डों को हटाने को कहेंगे।- **शुभम पाटीदार, एसडीएम।**

मंदिर परिसर में लक्ष्या सिक्यूरिटी एजेंसी ग्वालियर के निजी सुरक्षा गार्ड तैनात है। मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड से पूछा भी था कि शराब पीकर आया व्यक्ति अंदर कैसे चला गया तो वह बोले थे कि ऐसा लगा नहीं था। किसी तरह की लापरवाही के आरोप गलत है।-**राहुल रुनवाल, प्रबंधक, पशुपतिनाथ मंदिर समिति**

हमने इमरान पुत्र अब्दुल रशीद खलीफा निवासी नयापुरा के खिलाफ धारा 298 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं उसके पास से जहरीली शराब भी मिली है। - **कुलदीपसिंह राठौर, थाना प्रभारी, नई आबादी**

नर्सिंग छात्राओं ने लगाया रात में टेंट हटाने का आरोप, अंकसूची के लिए 10 दिन से धरना जारी

माही की गूंज, बड़वानी।

नर्सिंग महाविद्यालय की 25 जीएनएम छात्राएं अंकसूची नहीं मिलने से पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी हैं। धरने के दसवें दिन छात्राओं ने आरोप लगाया कि रात के समय उनका टेंट और अन्य सामान हटा दिया गया। छात्राओं का कहना है कि वे दशहरे के अवसर पर जल्दी चली गई थीं, लेकिन सुबह लौटने पर टेंट गायब मिला। उन्हें आशंका है कि धरना समाप्त कराने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से ऐसा किया गया है।

छात्रा पायल वास्कले ने बताया कि वे वर्ष 2020-21 के बैच की छात्राएं हैं। महाविद्यालय प्रबंधन पर लंबे समय से अंकसूची नहीं देने का आरोप है। लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं होने से छात्राएं नाराज हैं। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए धरना जारी रखेंगी, भले ही उन्हें जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़े।

छात्राओं के अनुसार, उन्होंने समय पर फीस जमा की है। प्रथम वर्ष की फीस पूरी भरी गई थी। कोरोना काल के दौरान फीस कम मिलने के बावजूद उन्होंने



भुगतान किया। द्वितीय वर्ष की 65 हजार रुपए की फीस भी जमा की गई। छात्रावास की सहायता राशि नहीं मिलने पर परिवार से पैसे लेकर किस्त भरी गई। तृतीय वर्ष में भी 10 हजार रुपए जमा किए गए हैं, लेकिन अब तक छात्रवृत्ति और आवास सहायता की राशि नहीं मिली है।

पायल वास्कले ने बताया कि महाविद्यालय के संचालक का कहना है कि छात्रवृत्ति नहीं आई है तो घर से फीस जमा करें। छात्राओं का कहना है कि उनका प्रवेश छात्रवृत्ति के आधार पर हुआ था। ऐसे में परिवार से बार-बार फीस भरना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि संचालक रतलाम में रहते हैं और छात्राओं से बातचीत करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं।

छात्राओं ने कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से संचालक को बुलाकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि वे केवल यह जानना चाहती हैं कि उनके शैक्षणिक दस्तावेज क्यों रोके गए हैं। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। कुछ छात्राओं ने निराशा में आत्महत्या और आत्मदाह जैसे कदम उठाने की धमकी भी दी है। छात्राओं की मांग है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी अंकसूची दिलाने की व्यवस्था करे और पूरे मामले की जांच कराए।

शहीदों के सम्मान में झुके शस्त्र, अधिकारियों और जवानों ने सिर झुकाकर किया नमन

माही की गूंज, खरगोन।

जिला पुलिस लाइन में बुधवार सुबह पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले 154 पुलिसकर्मियों को शोक परेड के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों के सम्मान में पहले शस्त्र झुकाए गए, इसके बाद अधिकारियों और जवानों ने सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। सभी ने एक मिनट का मौन रखकर शहीदों के बलिदान को याद किया।

कार्यक्रम सुबह 9 बजे आयोजित हुआ। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने 154 शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, पुलिस उपमहानिरीक्षक सिमाला प्रसाद और कलेक्टर गुरु प्रसाद सहित अन्य अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम में खरगोन जिले के शहीद जवानों के परिवारों को शॉल और नारियल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधान आरक्षक बसंत वर्मा के बलिदान को भी याद किया गया। उन्होंने वर्ष 2016 में नर्मदा नदी में डूब रहे 10 वर्षीय बालक को बचाने के प्रयास में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उपस्थित अधिकारियों और जवानों ने देश एवं समाज की रक्षा के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों के त्याग और समर्पण को नमन किया।



मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रावण बताकर कांग्रेस ने जलाया पुतला

माही की गूंज, खंडवा।



दशहरे के अवसर पर मंगलवार शाम कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांधी भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची के दुरुपयोग से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के साथ अन्याय किया गया है, जिसका असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया।

दशहरे का उदाहरण देते हुए प्रतिभा रघुवंशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में रावण को अपने ज्ञान और साम्राज्य का अहंकार था तथा सीता हरण उसके अंत का कारण बना। इसी तरह उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में मतदाता सूची के साथ अन्याय हो रहा है।

प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि केवल एक ही पुतला क्यों जलाया गया। इस पर प्रतिभा रघुवंशी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मेघनाद और कुंभकरण के नाम भी मतदाता सूची से कट गए हैं और उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने नए मतदाताओं के पंजीयन के लिए उपयोग होने वाले प्रपत्र-6 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अगली बार मतदाता सूची में मेघनाद और कुंभकरण के नाम जुड़ जाते हैं, तो कांग्रेस तीन पुतले जलाएगी। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को दूर करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।

लोक निर्माण विभाग के गोदाम में लगी आग, सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज जले

माही की गूंज, बड़वानी।



शहर में लोक निर्माण विभाग के गोदाम में मंगलवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा सामान, फर्नीचर और महत्वपूर्ण कागजात जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि आग पास में बने विभागीय आवासों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

गोदाम के पास स्थित आवासों में रहने वाले कर्मचारियों ने रात में धुआं उठता देखा, जिसके बाद तत्काल अग्निशमन दल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका का अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर पालिका अग्निशमन वाहन के चालक सचिन उटवाल ने बताया कि जब दल मौके पर पहुंचा, तब तक गोदाम में रखा सामान और कागजात जल चुके थे। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद बंद गोदाम में आग लगने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों ने आशंका जताई कि आग लगने के कारणों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि गोदाम काफी पुराना है और कई वर्षों से उसका रखरखाव नहीं हुआ है। विभाग के अन्य भवन भी जर्जर स्थिति में हैं। परिसर में पहले भी चोरी के प्रयास हो चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जर्जर भवनों और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण परिसर में रहना भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भवनों की मरम्मत कराने, गोदाम की सुरक्षा बढ़ाने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आग लगने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

दो दिन बाद खत्म हुआ बंद, एक माह में होगा प्रभावितों की संपत्तियों का सर्वे

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।



सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों से प्रभावित लोगों की मांगों को लेकर ओंकारेश्वर में दो दिन से जारी बंद मंगलवार शाम करीब 5 बजे समाप्त हो गया। प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच एक माह के भीतर प्रभावितों की संपत्तियों का सर्वे कराने पर सहमति बनी है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को मिलने वाले लाभ और पुनर्वास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। प्रभावित परिवारों को ओंकारेश्वर या आसपास के क्षेत्र में ही जमीन उपलब्ध कराने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांधाता विधायक नारायण पटेल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पंकज वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोनिका पारधी, षट्दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज सहित स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कुछ अधिकारी बैठक में दूरभाष एवं दृश्य माध्यम से जुड़े। बैठक दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई और ढाई बजे तक चली।

विधायक नारायण पटेल ने बताया कि एक माह के भीतर प्रभावितों की संपत्तियों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वे में स्थानीय नागरिकों, मकान मालिकों और संबंधित वार्ड पार्षदों को शामिल किया जाएगा। जमीन की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह तय होगा कि कौन कितना प्रभावित हुआ है और उसे किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है।

बैठक में प्रभावित परिवारों को ओंकारेश्वर या आसपास के क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के विकल्पों पर भी विचार किया गया। प्रशासन इसके लिए उपयुक्त स्थान तलाश रहा है। प्रभावित व्यक्ति वर्तमान में जितनी जमीन पर काबिज है, उसके अनुरूप जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

षट्दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज ने बताया कि स्थानीय नागरिकों की लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद सांसद, विधायक और कलेक्टर की अगली बैठक ओंकारेश्वर में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रभावितों को मिलने वाले लाभ और पुनर्वास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

बंद समाप्त होने के बाद मंगलवार शाम बाजार खुलने लगे और नगर में जनजीवन सामान्य होने लगा। अब स्थानीय नागरिकों को सर्वे और उसके आधार पर होने वाले निर्णयों का इंतजार है।

यूरोप में युवाओं के आक्रोश से उपजे प्रश्न

यूरोप में युवा सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं और उनका आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। फ्रांस में आंदोलन के गुस्से का शिकार बड़े पैमाने पर लंबे इतिहास को समेटे सरकारी इमारतें हुई हैं। हिंसा और आगजनी का दौर चल रहा है, भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। करीब 44 देशों के समूह को यूरोप कहा जाता है, जिसमें से फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और अल्बानिया में युवाओं का आंदोलन पूरे उफान पर है। बाकी देशों में भी युवाओं की नाराजगी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।



भाषा सिंह

इन तमाम देशों में जेनजी यानी वर्ष 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई युवा पीढ़ी के गुस्से की वजह एक नहीं, अलग-अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है और वह यह कि उनके जीवन से जुड़ी बुनियादी जरूरतों के बारे में उनके देशों की सरकारों का उदासीन रवैया है। जिस स्तर पर उनका गुस्सा भड़का है, उससे यह बात भी साफ है कि वे लंबे समय से अपने देश की सरकारों की गलत नीतियों से परेशान थे, पीड़ित थे और अब उनमें बदलाव चाहते हैं। बाकी दुनिया में चले जेनजी आंदोलनों की तरह यहां भी कोई एक संगठन या पार्टी उनका नेतृत्व करती नहीं नजर आ रही है। बहुत हद तक ये तमाम आंदोलन स्वतःस्फूर्त नजर आ रहे हैं।

फ्रांस में बढ़ती हिंसा-आगजनी को लेकर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सीधे-सीधे कहा कि इस तरह की हिंसा फ्रांस की जनता कैसे कर सकती है, यह अराजक तत्वों का गंदा खेल है, जिससे देश यानी फ्रांस को नुकसान हो रहा है। हालांकि, यहां मैक्रों यह बताने में असफल रहते हैं कि जो आंदोलन स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने के लिए शुरू हुआ, वह यहां तक कैसे पहुंचा और क्यों उनकी सरकार ने इस मुद्दे को शुरू में ही हल करने का प्रयास नहीं किया। अब तो जेनजी आंदोलन उनके हाथ से बाहर निकल गया है। प्रदर्शनकारियों ने लिमोज में 19वीं सदी के ऐतिहासिक सिटी हॉल में आग लगा दी। पेरिस के लग्जरी ब्रांडों की दुकानों, बैंकों व दूसरे भवनों में आग लगा दी। पेरिस के वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के अनुसार, शनिवार-रविवार को करीब 400 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। खराब स्कूलों और छात्रविरोधी शिक्षा नीति के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन रौद्र रूप हासिल कर चुका है।



किसी ने भी सितंबर में यह नहीं सोचा था कि स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी और विश्वविद्यालय में दाखिले के मुद्दों से शुरू हुआ यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर लेगा। उधर, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में युवाओं का गुस्सा महंगे घरों और ऊंचे किराये को लेकर फूटा। यहां के युवाओं का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वे किराये पर घर नहीं ले पा रहे हैं और उनका भविष्य चौपट हो रहा है। वहीं, बेल्जियम में सरकारी बजट में कटौती ने युवाओं और ट्रेड यूनियनों को सड़कों पर उतार दिया है। बेल्जियम में ट्रेड यूनियन लंबे समय से सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्से में थीं। छात्रों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है।

यूरोप इस समय जबरदस्त महंगाई की मार झेल रहा है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इटली में युवाओं का गुस्सा महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में आए उछाल और नौकरियों के संकट को लेकर फूटा है। उधर, अल्बानिया में जेनजी आंदोलन फ्रांस की ही तरह उग्र और हिंसक रूप ले चुका है। यहां व्यवस्था में जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है और वहां की अदालतें जिस तरह भ्रष्ट व्यवस्था के साथ खड़ी हैं, उसे लेकर युवाओं और बाकी जनता में बहुत गुस्सा है। अल्बानिया में आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को ही जला दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कोर्ट भ्रष्ट सरकार को बचाने का काम कर रहा है और जनता की बात नहीं सुन रहा है। इस हिंसा का विरोध भी हुआ है, लेकिन अभी बातचीत का दौर शुरू नहीं हो पाया है।

यूरोप और खास तौर से फ्रांस के विकास के मिथक को इस आंदोलन ने तोड़ा है, क्योंकि फ्रांस के एक छोटे से इलाके क्रेतेई के हाईस्कूल में छात्रों ने इसकी शुरुआत की। वे अपने स्कूल के खराब हालात से परेशान थे। टूटी इमारत, टूटी खिड़कियां, कम शिक्षक, स्कूलों में कॉकरोचों व चूहों का आतंक–इन सब पर उनका गुस्सा फूटा था। लंबे समय से स्कूली छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों में स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी थी। फ्रांस के स्कूलों में भी अमीरों के निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों की स्थिति में बहुत अंतर है। अंतर इलाकों के हिसाब से भी है। बड़े शहरों के पॉश इलाकों के स्कूल ठीक हैं, वहां अध्यापकों की उपलब्धता भी ठीक है। ऐसा दूर-दराज के इलाकों में नहीं है।

इस आंदोलन के दौरान यह सवाल भी सामने आया कि जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां के स्कूलों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। इन स्कूलों के शिक्षकों का भी कहना है कि कम आय वाले इलाकों में स्कूल होने की वजह से यहां पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन सरकार नहीं देती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। यह भेदभाव है, जिसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, तब से चर्चा के केंद्र में मैक्रों सरकार की गलत नीतियां भी आई हैं। इसके केंद्र में यह मांग है कि फ्रांस के सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा, सुरक्षित स्कूल और समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए नीतिगत बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है।

बड़ी संख्या में छात्र फ्रांस की विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। ज्यादा स्कूल खोलने की मांग तो हो ही रही है। छात्रों का मानना है कि सरकार शिक्षा के बुनियादी अधिकार पर ध्यान न देकर उनके भविष्य को चौपट कर रही है। स्कूलों में पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव और सरकार की अनदेखी ने युवा वर्ग के गुस्से को उबाल पर ला दिया, जिसकी वजह से कई जगहों पर आंदोलन ने बहुत उग्र रूप अख्तियार कर लिया। आज की तारीख में यह आंदोलन बेहद उग्र रूप ले चुका है और मौजूदा सरकार के हाथ-पैर फूले हुए हैं। एक राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया है।

इस जेनजी उभार-आंदोलन में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका है। दुनिया भर के जेनजी एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन भी करते हैं। यही वजह है कि जब सितंबर 2026 में फ्रांस में स्कूली शिक्षा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका असर आसपास के देशों पर भी बढ़ना शुरू हो गया और आज इसने यूरोप के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हर देश के जेनजी की मांग अलग है, लेकिन जज्बा एक ही है–हर सूरत में इंसाफ चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े।

आगे भगवान राम की तस्वीर, पीछे दिग्विजय सिंह और अमृता...

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा 20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू हुई। करीब 950 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 70 दिन में अयोध्या के राम मंदिर पहुंचने के लक्ष्य के साथ निकली इस यात्रा के पहले दिन धर्म, आस्था और सियासत के कई रंग दिखाई दिए। महाकाल के दर्शन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, संतों की मौजूदगी, कन्या पूजन और भंडारे के बाद यात्रा भजन, ढोल और धार्मिक झांकियों के साथ आगे बढ़ी। 20 अक्टूबर की सुबह उज्जैन में इस यात्रा की शुरुआत को करीब से देखने पहुंचा तो दिन की शुरुआत महाकाल मंदिर में दर्शन से हुई। इसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। यहां दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद आगे बड़े।

बालाजी गार्डन पहुंचने पर सबसे पहले संतों की मौजूदगी और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन दिखाई दिया। परिसर में बड़ी संख्या में संत समाज के लोग मौजूद थे। लोग सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग बनाने में जुटे थे। कहीं शिवलिंग निर्माण चल रहा था, तो कहीं पूजा-अर्चना की तैयारियां हो रही थीं। इस दौरान राम और शिव के भजनों की धुन सुनाई दे रही थी। धार्मिक माहौल के बीच लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे और उनका पूजन कर रहे थे। आयोजन की व्यवस्थाओं में दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह भी सक्रिय नजर आए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजा-अर्चना के बाद कन्या पूजन हुआ। इसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद वह समय आया, जब यात्रा को आयोजन स्थल से निकलकर सड़कों पर आगे बढ़ना था। दोपहर करीब एक बजे काफिला रवाना हुआ। इसके साथ उज्जैन से अयोध्या तक के लंबे सफर की औपचारिक शुरुआत हुई।

यात्रा के काफिले में सबसे आगे शिव-पार्वती की झांकी नजर आई। इसके साथ एलईडी वैन, डीजे, भजन मंडलियां, बैंड दल और ढोल चल रहे थे। काफिले में राष्ट्रीय ध्वज के साथ धर्म ध्वज भी दिखाई दिए। साधु-संतों का जत्था भी यात्रा में शामिल था। आगे भगवान राम की तस्वीर और पांच नदियों शिप्रा, नर्मदा, यमुना, गंगा और सरयू का जल लेकर लोग चल रहे थे। धर्म रथ के पीछे दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह, सैकड़ों संतों और समर्थकों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर आगे बढ़ते काफिले के साथ भजन और ढोल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धार्मिक प्रतीकों से सजे इस काफिले में यात्रा का घोषित उद्देश्य भी सामने आ रहा था। यह केवल उज्जैन से अयोध्या तक पहुंचने का सफर नहीं है। इसके जरिए दिग्विजय सिंह मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में जवाबदेही जैसे सवाल भी उठाना चाहते हैं। उज्जैन के अलग-अलग मार्गों से गुजरते हुए यात्रा को शाम को कानीपुरा पहुंचना था। पहले दिन एक तरफ पूजा-पाठ, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और संत समाज की मौजूदगी दिखाई दी, तो दूसरी तरफ सड़कों पर आगे बढ़ता धार्मिक काफिला और उसके साथ जुड़ा राजनीतिक संदेश भी नजर आया।



मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता पर सवाल

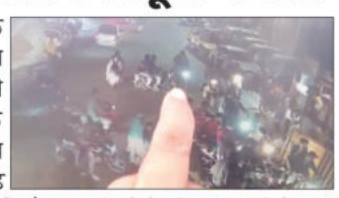
दिग्विजय सिंह की इस यात्रा का नाम सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा है। उनके घोषित मुद्दों में मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में जवाबदेही की मांग शामिल है। वह राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था और कथित चंदा चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही वह वोट चोरी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत महाकाल के दर्शन और पार्थिव शिवलिंग निर्माण जैसे धार्मिक आयोजनों के बीच हुई, लेकिन इसके साथ मंदिरों की व्यवस्था से जुड़े सवाल भी जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह इस यात्रा के जरिए इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाना चाहते हैं। हालांकि, चढ़ावे या चंदे में गड़बड़ी से जुड़े आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक उनके समर्थन में साक्ष्य सामने न आएं। इस लिहाज से यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले सवालों के साथ संबंधित संस्थानों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

दिग्विजय सिंह की राजनीति में धर्म का मुद्दा नया नहीं है। उनके आलोचक अक्सर उन्हें सनातन विरोधी कहकर निशाना साधते रहे हैं। दूसरी तरफ, उनकी नर्मदा परिक्रमा और पंढरपुर में भगवान विट्ठल की यात्रा जैसे धार्मिक प्रसंग भी उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। अब उज्जैन से अयोध्या तक की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा ने उन्हें एक बार फिर धर्म और राजनीति से जुड़ी बहस के केंद्र में ला दिया है। इस यात्रा को लेकर सवाल भी हैं कि क्या यह धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है, मंदिरों की व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को प्रमुखता से उठाने का प्रयास है या इसके साथ राजनीतिक संदेश भी जुड़ा है। यात्रा के पहले दिन उज्जैन में धार्मिक आयोजनों और संतों की मौजूदगी के बीच इन सभी पहलुओं की झलक दिखाई दी। हालांकि, यात्रा का वास्तविक प्रभाव आगे के पड़ावों और वहां उठाए जाने वाले मुद्दों से ही साफ होगा।

उज्जैन से अयोध्या तक करीब 70 दिन का सफर

दिग्विजय सिंह की योजना करीब 70 दिन में लगभग 950 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या के राम मंदिर पहुंचने की है। इस दौरान उन्हें अलग-अलग पड़ावों पर लोगों से संवाद करने और अपने मुद्दे रखने का अवसर मिलेगा। उज्जैन में यात्रा की शुरुआत धार्मिक रंग में रंगी दिखाई दी। महाकाल के दर्शन से लेकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, कन्या पूजन, भंडारे और भजन-कीर्तन तक, पहले दिन का कार्यक्रम आस्था के अलग-अलग रूपों से जुड़ा रहा. इसके साथ मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा भी यात्रा के उद्देश्य के रूप में सामने आया। अब इस लंबे सफर में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि धार्मिक आयोजनों के बीच दिग्विजय सिंह मंदिरों की व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों को किस तरह उठाते हैं। उज्जैन से अयोध्या तक की यह यात्रा इसलिए ध्यान खींच रही है, क्योंकि इसमें आस्था, मंदिर प्रबंधन और राजनीति के सवाल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

रॉन्ग साइड को लेकर खूनी बवाल



भोपाल। भोपाल में ट्रैफिक नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते चाकूबाजी तक पहुंच गया। राजधानी के मोती मस्जिद चौराहे के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर बाइक सवारों और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तीन युवकों ने बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में बाइक सवार घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

यह घटना भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र की है। मोती मस्जिद चौराहे के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर बाइक सवारों और युवकों के बीच विवाद हुआ था। शुरुआत में मामला कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि विवाद के दौरान तीन युवकों ने बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बाइक सवार घायल हो गए. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले।

हमले के बाद फरार हुए तीन आरोपी

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। तलैया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस का मुख्य प्रयास आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना है। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। फुटेज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कौन-कौन शामिल था और आरोपी घटना के बाद किस रास्ते से फरार हुए।

पुलिस आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान के लिए जरूरी सुराग मिल सकें। सीसीटीवी फुटेज से घटना के दौरान मौजूद लोगों और वारदात के घटनाक्रम की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सकेगी।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मोती मस्जिद के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड को लेकर बाइक सवारों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद तलैया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर चाकूबाजी तक कैसे पहुंचा, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। तीनों आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही विवाद की पूरी वजह और हमले से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।



रोप-वे परियोजना की लागत 69 से बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से सीधे महाकालेश्वर मंदिर तक हवाई रास्ते से पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी 'महाकाल रोप-वे परियोजना' एक बार फिर आगे बढ़ी है। दो साल में मात्र 2 प्रतिशत काम करने वाली ओडिशा की एमएस इंफ्राइंजीनियर्स कंपनी ठेका निरस्त करने के बाद नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ने काम पुनः प्रारंभ कराने के लिए प्रोजेक्ट की लागत 69 करोड़ रुपये बढ़ाकर 258.37 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी कर दिया है।

जिम्मेदार अधिकारी पर सरकार अब भी मेहरबान है

यानी समय पर काम न कराने से सरकार की जेब पर 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर सरकार अब भी मेहरबान है। क्योंकि उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है। इच्छुक निविदाकारों से 28 अक्टूबर 2026 तक निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

दो साल में कंपनी 2 फीसदी काम भी पूरा नहीं कर सकी

मालूम हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 24 फरवरी 2022 को महाकाल रोप-वे परियोजना की घोषणा की थी। तब इसके लिए 188 करोड़ 95 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में ओडिशा की मेसर्स इंफ्राइंजीनियर्स कंपनी को निर्माण, संचालन और रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन दो साल में कंपनी 2 फीसदी काम भी पूरा नहीं कर सकी।

ठेकेदार फर्म और विभागीय अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं रहा

इसका मुख्य कारण ठेकेदार फर्म और विभागीय अधिकारियों के बीच तालमेल और कागजी खानापूर्ती समय पर न होना सामने आई। बहरहाल इसी साल जून माह में ठेका निरस्त करने के बाद अब प्रोजेक्ट नई एजेंसी तय कर आगे बढ़ाने के लिए दोबारा टेंडर काल किया गया है। इस बार भी रोप-वे निर्माण की समय सीमा दो वर्ष निर्धारित की है। वर्ष 2028 में महाकुंभ सिंहस्थ प्रारंभ होना है।

ये प्रोजेक्ट महाकुंभ से पहले पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है

यानी अगले माह नवंबर में ठेकेदार तय कर कार्य आदेश जारी होता तो भी ये प्रोजेक्ट महाकुंभ से पहले पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। हां, यदि साइट पर दिन-रात काम चलाया जाए तो काम हो भी सकता मगर ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि मामला महाकाल क्षेत्र और रेलवे स्टेशन से जुड़ा है और उज्जैन वो शहर है जहां 12 महीने तीज-त्योहार भव्यता से मनाए जाते हैं और हर दिन लाखों पर्यटक यहां महाकाल दर्शन करने आते।

सालभर तक कागजों में उलझा रहा काम, किसी अफसर पर नहीं गिरी गाज

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पिछली बार टेंडर खुलने के लगभग एक साल बाद तक धरातल पर काम ही शुरू नहीं हो सका था। पूरी प्रक्रिया केवल कागजी खानापूर्ति में ही बीत गई। निर्माण एजेंसी द्वारा करीब 10 नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ठेकेदार ने काम से हाथ पीछे खींच लिए। गंभीर लापरवाही और परियोजना में विलंब के बावजूद किसी भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है।

13 में से केवल 3 टॉवर, लोकेशन पर खुदे थे गड्ढे

मौके पर स्थिति यह रही कि इंदौर गेट रेलवे स्टेशन और माधवगंज स्कूल के पास बोर्डिंग स्टेशन के लिए डेढ़ साल पहले खोदे गए गड्ढे आज भी जस के तस पड़े हैं। 13 प्रस्तावित टावर लोकेशनों में से केवल 3 स्थानों पर ही सीमित खुदाई हुई थी। काम ठप होने और ठेकेदार द्वारा असमर्थता जताने के बाद जून 2026 में ठेका निरस्त कर अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

अब ऐसा होगा नया स्वरूप

नए टेंडर के अनुसार, रोप-वे की लंबाई को 1.76 किलोमीटर से बढ़ाकर 1.9 किलोमीटर (1900 मीटर) निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए ट्रांजित टाइम 5 से 7 मिनट का तय किया गया है। परियोजना के तहत 10 यात्री क्षमता वाले गोंडोला कोच, 3 बोर्डिंग स्टेशन, पार्किंग, प्रतीक्षालय और फूड जोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं। सिंहस्थ 2028 से पहले श्रद्धालुओं के लिए इस सुविधा का शुरू होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

होटल से नाबालिग लड़की के साथ पकड़ाया युवक



माही की गूंज, उज्जैन। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र के दूधतलाई स्थित होटल जय जगदीश में मंगलवार रात नाबालिग लड़की के साथ एक युवक के मिलने पर हंगामा हो गया। सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होटल पहुंचे। उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान शाजापुर निवासी मोइन के रूप में बताई गई है। पुलिस ने लड़की के माता-पिता और मामा को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कमरा नंबर 303 में मौजूद थी नाबालिग

हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अर्जुन सिंह भदौरिया के मुताबिक संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि होटल के कमरा नंबर 303 में नाबालिग लड़की मौजूद है। अर्जुन सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में राहुल सिसोदिया, सौरभ तंवर, मनोज जाट, प्रतीक मिश्रा, पुजारी अनिमेष अंगद द्विवेदी सहित अन्य कार्यकर्ता होटल पहुंचे। संगठन का दावा है कि युवक ने शुरुआत में अपनी सही पहचान नहीं बताई। आधार कार्ड देखने पर उसका नाम मोइन सामने आया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी और दोनों को थाने ले जाया गया।

मोबाइल और नशीले पदार्थ मिलने का दावा

संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि युवक पहले से शादीशुदा है और उसके मोबाइल में अन्य लड़कियों के संपर्क भी मिले हैं। युवक के पास से गांजा और गोगो नाम का नशीला पदार्थ मिलने की बात भी कही गई है। हालांकि, इन दावों की पुलिस से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गरबा आयोजनों में साथ जाने की बात

अर्जुन सिंह भदौरिया के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग लड़की पिछले तीन दिनों से गरबा करने जा रही थी। उसने आस्था और राजाराम में गरबा करने जाने की बात बताई। भदौरिया ने दावा किया कि युवक भी इस दौरान उसके साथ गरबा करने गया था।

पुलिस ने परिजनों को सौंपा

देवास गेट थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर परिहार के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में एक नाबालिग लड़की रुकी है और उसके साथ एक युवक भी आया है। संगठन के कार्यकर्ता दोनों को थाने लेकर आए थे। पुलिस ने लड़की के माता-पिता और मामा को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मतांतरण के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

माही की गूंज, झाबुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरण के बाद आरक्षण का लाभ लेने वाले मुद्दे पर ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि, हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मतांतरण करने वाला व्यक्ति अपने पुराने पिछड़ेपन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि, इस्लाम स्वीकार कर लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति राज्य के अधिसूचित मुस्लीम पिछड़ा वर्ग समुदायों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन जाता। मतांतरण से पहले की जाति या सामुदायिक पहचान को अपने आप किसी दूसरे धर्म के पिछड़ा वर्ग समुदाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

मतांतरण का मुद्दा वर्षों से चर्चा में है, मुख्यतः जनजातिय क्षेत्रों में अधिकतर इन मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद होती सुनाई देती है। जहां अनेक आदिवासी ग्रामीणों को लोभ लालच में लेकर मतांतरित किया जाता है और उनके पिछड़ेपन का ही लाभ उठाकर उनको आरक्षण की सुविधा दिलवाई जाती रही है। इसका विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डिलिस्टिंग की मांग की और बीते कई वर्षों से आदिवासी जिलों में आंदोलन भी किया, क्योंकि भोलेभाले ग्रामीण आदिवासी अपनी मजबूरी और लाचारी में मिशनरियों के बहकावे में आकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर मतांतरित होते हुए अन्य सामाजिक व्यवस्था पर विश्वास करते हुए। उस व्यवस्था में जीवन यापन कर अपने इष्ट तक को बदल देते हैं, और मतांतरित हुए वहीं लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए आगे आ जाते हैं जिससे सरकार द्वारा दिया गया वह लाभ जो जनजाति ग्रामीणों को मिलने वाले होते हैं वो उन मतांतरित लोगों को मिलते हैं इस तरह वे मतांतरित लोग दोहरा लाभ लेते हैं।

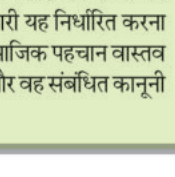


धर्म, पंथ, मत, मजहब यह सभी जीवन जीने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां है। वातावरण और पृष्ठभूमि और धरती के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए पंथ या मतों का जन्म हुआ। जैसे लगभग 1400 वर्ष पहले इस्लाम का जन्म अरब में हुआ जहां रेत होने से दिन गर्म होते इसलिए वहां रात के चांद ने उन लोगों को काम करने के लिए सहयोग किया, और इसी वजह से चांद उनका पुज्यनीय हो गया। जबकि भारतीय पद्धति में तो सदियों पहले ग्रहों नक्षत्रों का ज्ञान रखते हुए काल गणना की गई। ईसाई समुदाय जो लगभग 2000 वर्षों पहले दूनिया में आया और सुर्य को अपना प्रमुख देवता मानते हुए सन डे को प्रार्थना पूजा का प्राविधान रखा, क्योंकि बर्फ से ढके क्षेत्रों में सुर्योदय होने के बाद ही सुकून मिलता था। अपने-अपने क्षेत्रों और वातावरण के अनुरुप इन पंथो ने अपने समाज को चलाने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को बनाया, किंतु बाहर देशों के नियम भारत देश में रहने वालों पर लालच देकर थोपना उनका मतांतरण करवाना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए घातक है।

भारत में मूलरुप से निवास करने वालों में से जिन लोगों ने भी मतांतरण किया है वो पहले हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले रहते थे किंतु भय और लोभ के कारण वे अन्य सामाजिक व्यवस्था में मतांतरित हो गए और आरक्षण का लाभ लेने लगे। जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया था कि मतांतरण के बाद किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु की सरकार ने याचिका दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि, किसी भी व्यक्ति के मतांतरण के पश्चात उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बुद्धीजीवियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय व्यापक असर डालने वाला और दूरगामी प्रभाव वाला है। यह निर्णय अनुसूचित जाति वर्ग से मुस्लिम और ईसाई पंथ अपनाने वालों की उस मांग पर असर डालेगा जिसमें वे अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की मांग को उठा रहे हैं। हालांकि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम को आरक्षण मिलने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

कोर्ट ने इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों और भारतीय मुस्लिम समाज की सामाजिक संरचना के बीच अंतर स्पष्ट किया है निर्णय में कहा कि, इस्लाम में मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार जन्म, वंश या नस्ल नहीं है बल्कि धर्मपरायणता और आचरण है। फिर भी भारत में कुछ मुस्लिम समुदायों के बीच वंशानुगत सदस्यता, पारम्परिक व्यवसाय, अपने समुह में विवाह और सामाजिक स्थिति के अलग-अलग स्तर जैसी विशेषताएं भी विकसित हुई है। कोर्ट ने कहा है कि, इन सामाजिक संरचनाओं के अस्तित्व से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पूरे मुस्लिम समाज में हिंदू जाति व्यवस्था जैसी एक समान व्यवस्था है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में महत्वपूर्ण बात यह कही है कि, मतांतरण धार्मिक जुड़ाव स्थापित करता है, परंतु अपने आप किसी धर्म के अंदर किसी विशेष ऐतिहासिक सामाजिक समुदाय की सदस्यता साबित नहीं करता है। पीठ ने कहा है कि, सरकारी आदेश में हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पहले से मौजुद पिछड़ेपन को दूसरे धर्म के किसी विशेष अधिसूचित समुदाय की सदस्ता का पर्याप्त आधार मान लिया गया।



रिंकेश बैरागी

किसी विशेष समुदाय के सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण उसकी वास्तविक स्थिति और वस्तुनिष्ठ मापदंडो के आधार पर होना चाहिए। जमात यह प्रमाणित कर सकती है कि, किसी व्यक्ति ने इस्लाम स्वीकार किया है परंतु केवल उसके प्रमाणपत्र के आधार पर सार्वजनिक लाभ की पात्रता तय नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा है कि किसी निजी धार्मिक संस्था या जमात को वैधानिक आरक्षण के लिए किसी व्यक्ति की सामुदायिक स्थिति का अंतिम निर्धारण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

हालांकि, मध्यप्रदेश में झाबुआ, आलीराजपुर सहित आदिवासी अंचलों में मतांतरण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। इन जिलों में आदिवासियों के ईसाई धर्म अपनाने को लेकर विभिन्न सनातनी संगठनों और जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा करिब 15 वर्षों से डिलिस्टिंग और घर वापसी जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।

बहरहाल कोर्ट ने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि पुनः मतांतरण पर स्वतः लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदु सामाजिक व्यवस्था से गैर हिंदू धर्म अपनाने के बाद फिर से हिंदू धर्म में लौटता है तो अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पाने के उसके अधिकार का निर्णय पहले की स्थिति के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी को तथ्यों की स्वतंत्र जांच करनी होगी। प्राधिकारी यह निर्धारित करना होगा कि उसकी मूल जाति या सामाजिक पहचान वास्तव में फिर से स्थापित हुई है या नहीं और वह संबंधित कानूनी शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

भ्रष्टाचारी रावणों से बचने अब रावण भी करने लगे आत्मदाह

विजयादशमी पर रावण ने बदला अपना मूड या चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट

माही की गूंज, झाबुआ।
मुज्जमिल मंसुरी

विजयादशमी (दशहरा) हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस त्यौहार को लेकर पौराणिक कथाएं और महत्व बहुत है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह त्यौहार उत्साह, उल्लास और अल्हड़पन का प्रतीक बनकर रह गया है। दशहरे के दिन अब केवल रावण का ही दहन होता है। जबकि मेघनाद और कुंभकरण अब इस आयोजन का हिस्सा बनने से वंचित है। पूरे देश में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मान्यताओं के साथ दशहरा मनाया जाता है। देश के कई क्षेत्रों में यह पर्व दुर्गा पूजा के समापन और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस के संहार के रूप में भी मनाया जाता है। कुल मिलाकर विजयादशमी का यह त्यौहार असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

मगर यह कलयुग है, इस दौर में एक पुतले के दहन मात्र को दशहरा माना जा रहा है। जबकि इस युग के हर देह में एक रावण छुपा बैठा है। हद तो तब हो जाती है जब बुराई के प्रतीक रावण के पुतला निर्माण में भी भ्रष्टाचार हो जाता है। पिछले कुछ सालों में जब इस तरह की खबरें पढ़ने या लिखने में आती थी तब मन में यही भाव उत्पन्न होते थे कि, यह रावण भी सोचता होगा कि, हर देह में रावण बैठा है लेकिन ये मुर्ख सिर्फ मेरे पुतले को जलाकर ही खोखली प्रसन्नता हासिल कर रहे है। रावण का प्रतीकात्मक पुतला भी यह सब देखकर आंसू बहाता होगा कि, इस कलयुग में अब राम स्वरूप तो रहे नहीं रावण ही रावण को फूंक रहे है। यह कल्पना और भाव अब हकीकत बनते दिखाई दे रहे है।

मंगलवार को देश सहित इस आदिवासी अंचल में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह-जगह बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान जिले में कहीं कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई और त्यौहार पूरे अंचल में शांति पूर्वक सम्पन्न हो गया। लेकिन अबकी बार रावण दहन के दौरान जो घटनाक्रम हुए वह बहुत ही चौकाने वाले दिखाई दिए। लोगों ने इसे कहीं अपशगुन तो कहीं मिथक टिप्पणियों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर की। जिले के थांदला में दशहरा मैदान पर उस समय लोग चौक गए जब बिना रामजी के बांण चलाए ही रावण धधक-धधक के जलने लगा। ऐसा ही कुछ झाबुआ में भी देखने को मिला कि, रावण का पुतला पुरी तरह जला ही नहीं, उसका एक हाथ और आधे सिर बिना जले ही रह गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई मजेदार टिप्पणियां भी की।

अब सवाल यह कि, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राम जी के मारे बगैर ही रावण मर जाए...? थांदला में जब दशहरा मैदान पर रावण दहन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, दहन में अभी कुछ समय बाकी



था। राम जी स्वरूप की सवारी आना बाकी थी। बचे इस थोड़े समय में नगरपरिषद द्वारा रंग-बिरंगी आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान आतिशबाजी से निकली चिंगारी रावण के पुतले तक पहुंच गई और सब कुछ अधूरा रह गया। ना राम जी समय पर पहुंच पाए और ना नगरपरिषद की रंग-बिरंगी आतिशबाजी पूरी हो सकी और रावण खुद ही जलकर राख हो गया। नगरपरिषद का अमला यकायक सक्ते में आ गया कि, अब क्या...? रामजी पहुंचे नही और रावण ध्वस्त...! लोगों ने यह नजारा शायद पहली बार ही देखा होगा कि, रावण खुद आत्मदाह कर रहा हो। एक तरफ प्रशासनिक अमला और नगरपरिषद की टीम रावण के आत्मदाह करने के सदमें से बाहर नहीं आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर उपहास शुरू हो गया तथा प्रशासन और नगरपरिषद की नाक कट गई।

लोगों में जमकर हंसी-ठिठोली के साथ यह चर्चा चल पड़ी कि, आखिर रावण भी रामजी को पहचानता था, तो उसने इस बात को मंजूर नहीं किया कि, कोई भ्रष्ट उर्फ कलयुगी रावण और भ्रष्टाचार में लिप्त कोई रावणी संस्था उसे जलाए, सो उसने खुद आत्मदाह कर लिया। लोगों ने ठहाकों के साथ कहा कि, इस दौर में रावण भी जानता था कि, कोई राम नहीं है, सबके सब मेरे ही भाई है बस फर्क यह है कि मैं, सतयुग का अकेला रावण था और यह सब भ्रष्टरूपी कलयुगी रावण है। जिस तरह विभिषण ने त्रेतायुग में मेरी ही लंका जलवाई थी, आज भी उसी तरह कलयुग में मेरे प्रतीक जिनके दिल और मनों में ठूस-ठूस के बुराई भरी हुई है, मुझे जला रहे है। इससे अच्छा तो यह कि मैं खुद आत्मदाह कर लूं।

इधर विजयादशमीं पर जिला मुख्यालय पर होने वाले आयोजन में सबकुछ सही और सटीक था। कार्यक्रम का हर भाग अपने समय पर पूरा होता दिखाई दिया। पीजी कॉलेज मैदान पर अथाह भीड़ रावण दहन देखने के लिए पहुंची। किसी तरह की कोई भगदड़ या दुर्घटना के कोई समाचार सामने नहीं आए। लेकिन यहां भी लोगों ने रावण दहन को लेकर खूब चुटकुलेबाजी की। मामला महज इतना सा था कि, इस बार जिला मुख्यालय पर होने वाले रावण दहन में रावण का एक हाथ और एक तरफ के पांच सर नहीं जल सके। जब लोगों को यह खबर मिली कि, जिले के थांदला में रावण समय के पूर्व खुद ही जल गया तो लोगों ने दोनों घटना को जोड़ना शुरू कर दिया। लोग ठहाके लगाते हुए कह रहे थे कि, थांदला में रावण ने आत्मदाह कर लिया तो झाबुआ के रावण ने भी बचकर भागने की पूरी कोशिश की मगर वह सफल नहीं हो सकता। जिले के बामनिया में रावण को जलाने के लिए भारी मशक्कतें भी देखने को मिली। तीनों घटनाक्रम को एक साथ देखें तो यह लगता है जैसे रावण अब जलना ही नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग मनोरंजक टिप्पणी करते हुए लिख रहे है कि ''हर बार मैं ही क्यूं जलूंगा किसी और को ढूंढ लाओ।''

लोगों ने जिले में घटी इन घटनाओं पर कड़े सवाल भी उठाए हैं। थांदला में समय के पहले नगरपरिषद की आतिशबाजी में स्वाहा हुए रावण पर कड़ा आक्रोश जताया। सवाल उठाए कि ''रावण का असमय दहन आतिशबाजी में हुई लापरवाही का नतीजा है तो नगरपरिषद इस नुकसान की भरपाई किससे करवाएगी...?'' लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिले में हुई इन रावण दहन में लापवाही की घटनाओं को आड़े हाथों लिया है। कहीं नगरपरिषद, नगरपालिका की खिंचाई हो रही है तो कहीं नौसिखियों की राजनीति की भेंट चढ़ना माना जा रहा है। वर्षों पुरानी परम्परा में प्रशासनिक लापरवाही ने इस बार सेंध लगा दी। थांदला में आक्रोशित नगरवासियों ने नारेबाजी करते हुए अस्पताल चौराहे पर खाली बॉक्स का प्रतिकात्मक रावण बनाकर दहन किया। इससे लोगों में उपजे आक्रोश को समझा जा सकता है।

हालांकि यह घटनाक्रम अपने आप में अनूठे थे, लेकिन जिले में इससे पहले भी रावण दहन हमेशा से ही चर्चा में रहा है। नगरपालिका और नगरपरिषदों में अक्सर रावण निर्माण के टेंडरों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोप लगते रहे है। रावण के पुतला निर्माण को लेकर हर नगरपरिषद और नगरपालिका में हजारों से लेकर लाख तक के या उससे अधिक के टेंडर होते है। यह बात कोई छुपी नहीं है कि हर टेंडर में बागड़ बिल्लों का कमीशन होता है। अक्सर कमीशन की बंदरबांट को लेकर भ्रष्टों की जूतम पैजार सड़कों तक सुनाई दे जाती है। इस भ्रष्टाचार के माहौल में बुराई के प्रतीक रावण को दहन करने में भी भ्रष्टाचार हो जाता है। असल में रावण दहन का जो उद्देश्य है वह इस दौर में शायद ही अब कभी पूरा होता दिखाई दे। क्योंकि अब हर तरफ भ्रष्ट रावणों का कब्जा है, और यही भ्रष्ट रावण पूरी तरह से यह मन मष्तिस्क में ठान चुके है कि, रामजी अब इस कलयुग में नहीं आने वाले। मतलब अब भ्रष्ट रावण ही भ्रष्टाचार करके रावण का पुतला बनवाएंगे और फिर यही भ्रष्ट रावण, राम का रूप धर भ्रष्टाचार से बने इस प्रतिकात्मक रावण को जलाएंगे। यानि अब असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का यह कोई प्रतीक नहीं, रावण ही रावण से आपस में टकराएंगें।

कूड़ा करकट और खरपतवार से भरी नहरे, सफाई के नाम सिर्फ रस्म अदायगी

माही की गूंज, बरवेट।
जगदीश प्रजापत

मानसून सीजन में औसत से कम बारिश होने और जलाशयों के खाली रहने के कारण रबी फसल के उत्पादक किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा केवल दो पानी (सिंचाई के लिए पानी) देने के फैसले ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। क्योंकि गेहूं और अन्य मुख्य रबी फसलों को पूरी तरह पकने के लिए कम से कम 4 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इधर डेम से निकलने वाली नहर से सैकड़ों गांव के हजारों किसानों को सिंचाई का उपयोग करते है। इधर विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह के यानी दीपावली के पहले नहरों में पानी सप्लाई करेगा। जिसके लिए नहरों की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

कूड़ा करकट और खरपतवार से भरी नहरे

माही डेम से कई गांवों से होते हुए निकली नहरों में झाड़ियां व खरपतवार उग आई है। वहीं नगरीय क्षेत्र में लोगों द्वारा कूड़ा-करकट भी फेंका जाने के चलते इनकी सूरत ही बदल गई है।

विपिन पाटीदार ईई जलसंसाधन विभाग झाबुआ ने बताया, आगामी दिनों में किसानों को पानी भी नहरों से दिया जाना है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की साफ-सफाई का कार्य भी शुरू करवा दिया है। विभाग को उम्मीद है कि, एक नवम्बर के पहले नहरों की साफ-सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। कम बरसात होने के कारण माही डैम में पानी का लेवल औसत स्तर से काफी



कम है। रबी सीजन के लिए किसानों को दो पानी दीए जायेंगे। नहरों की सफाई समय से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। नहरों की साफ-सफाई का काम शुरू करवा दिया है, एक नवंबर के बाद दीपावली के पहले पानी छोड़ा जाएगा।

0 से 18 किलोमीटर तक ज्यादा सीपेज होता है पानी

माही डैम से निकलने नहरों की स्थिति काफी जर्जर है। सबसे ज्यादा लीकेज 0 से 18 किलोमीटर तक हो रहा है। क्योंकि वहां पर हार्ड रॉक और नहरो की गहराई ज्यादा है। वही ग्राम महुडीपाड़ा से बरवेट-बावड़ी मुख्य केनाल की स्थिति काफी जर्जर है। केनाल की सीमेंट-कांक्रीट कई जगह निकल चुकी है। जिससे लीकेज सीपेज के साथ फूटने की स्थिति बनी रहती है। पानी की कमी के चलते चने की बोवनी करने पर ध्यान दे। माही नहरों से सिंचाई के लिए दो पानी दिए जा रहे है, ऐसे में गेहूं पकेंगे नही। इसी स्थिति में किसानों को चने की बोवनी करनी चाहिए। चने की बोवनी से पहले खेतो में पलेवा करे उसके बाद बोवनी करे। जिससे चने की फसल पकने की संभावना बढ़ सकती है। माही नहरों में पानी छोड़ने से सब्जी उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। क्योंकि नहरों में पानी छूटते ही छोटे-मोटे नदी-नाले रिचार्ज हो जाएंगे। जिससे वे अपनी सब्जी की फसलों को दो माह तक पानी दे सकेंगे। जिन्होंने सब्जी, फल, कपास आदि की फसल लगा रखी है उन किसानों को लाभ मिलेगा।

माही मुख्य बांध की जल भराव स्थिति

वर्तमान जल स्तर- 446.75मीटर।
पूर्व जल स्तर- 451.50 मीटर।
जीवंत क्षमता -57.10,135,.60 एमसीएम (मिलियन घन मीटर)।
माही बांध में जल भराव -51प्रतिशत।



डॉग अभिरक्षा में चौकी...!

माही की गूंज, खवासा।

कई बार कैमरे की नजर में ऐसे फोटो कैद हो जाते हैं जो दुर्लभ भी होते हैं और उनके कई अर्थ व्यक्ति के अपने-अपने नजरिये के अनुसार निकाले जा सकते हैं।

ऐसा ही एक फोटो माही की गूंज के कैमरे में कैद हुआ। जिसमें खवासा पुलिस चौकी पर जिस समय चौकी प्रभारी पर्दे की आड़ में अपने कक्ष में बैठे थे, कुछ व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आए वह भी चौकी पर बाहर लगी कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं छांव में डॉग परिवार के 4 सदस्य आराम फरमा रहे हैं। और कहे तो पुलिस



चौकी की अभीरक्षा भी करते नजर आ रहे हैं। हम इस फोटो का कोई अर्थ नहीं निकालते हैं लेकिन यह फोटो अपने आप में कई अर्थों को बयां करता है।

जब यह फोटो माही की गूंज के कैमरे में कैद होते चौकी प्रभारी को महसूस हुआ तो वह भी मुस्कुरा दिए और प्रतिनिधि से हास्यप्रद स्थिति में चर्चा करते हुए पूछने लगे क्या आपने फोटो खींच लिया...? और स्टाफ को कहा चौकी में बैठे डॉग परिवार (कुत्ते) को भगाओ और स्टाफ ने डॉग परिवार (कुत्ते) को भगा दिया। जिसके बाद साहब ने आत्मियता के साथ अन्य चर्चाओं के साथ जब तक चाय नहीं पिलाई तब तक हमारे प्रतिनिधि एवं एक अन्य पत्रकार साथी को चौकी से नहीं आने दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422